UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

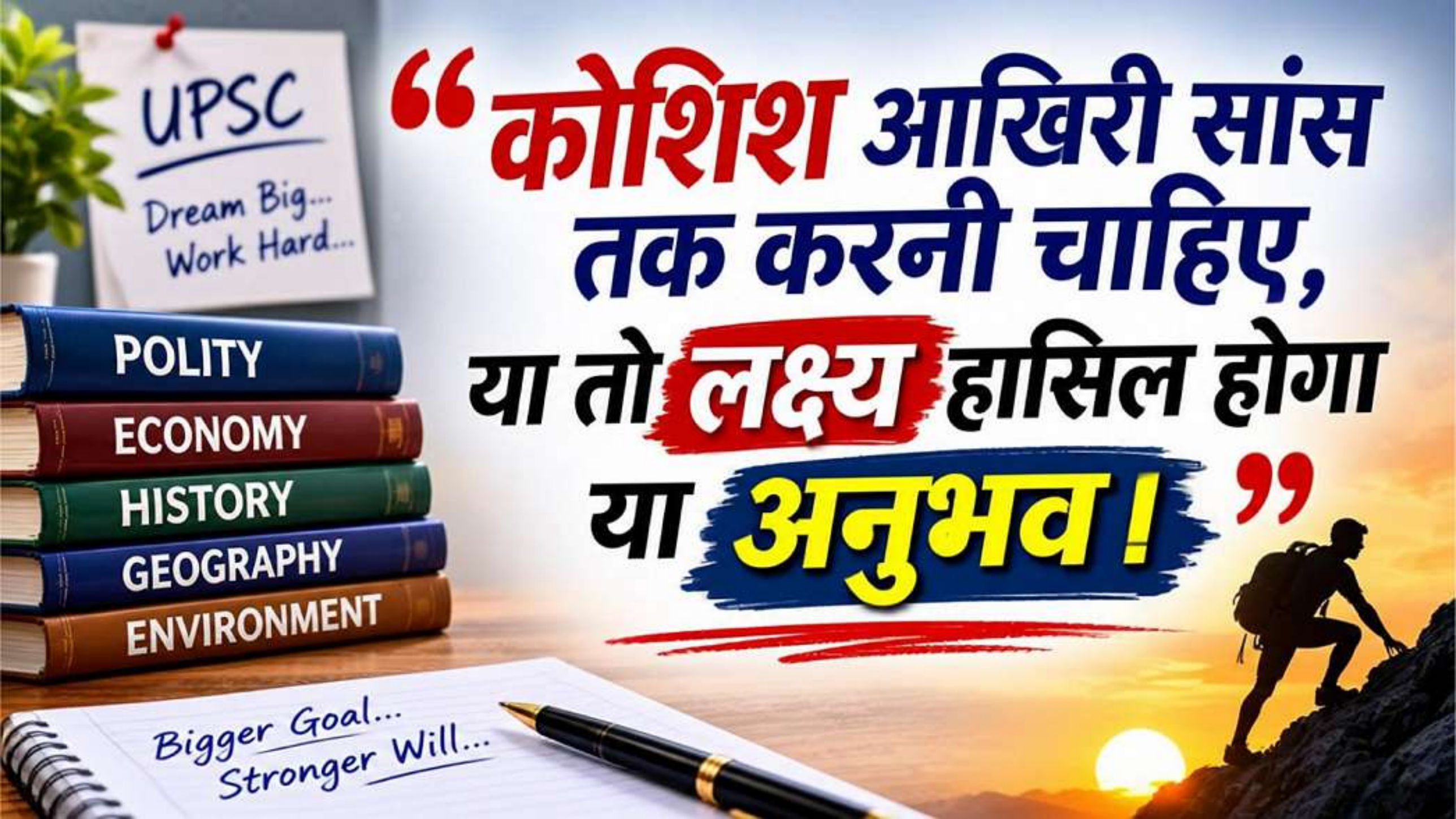
By **Faiyaz Sir**



The Indian EXPRESS | THE HINDU | pib PRESS INFORMATION BUREAU

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD
STAY PREPARED


UPSC
Dream Big...
Work Hard...
POLITY
ECONOMY
HISTORY
GEOGRAPHY
ENVIRONMENT
Bigger Goal...
Stronger Will...
“कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए,
या तो लक्ष्य हासिल होगा
या अनुभव!”

आज क्या पढ़ेंगे?

- ☐ 'नेचुरोपैथी'
- ☐ Microfinance
- ☐ Transgender Health Rights
- ☐ ECI/SIR
- ☐ 10th Schedule
- ☐ Earth shot Prize
- ☐ India-Japan 2+2 Dialogue
- ☐ 3rd Advanced Estimate of Area and Production of Horticultural Crops
- ☐ Malaria
- ☐ VOYAGER-1
- ☐ Lineshine – Super Cumputer
- ☐ IN-SPACe – ISRO
- ☐ Bangladesh 1st Nuclear Plant
- ☐ ASEAN Summit
- ☐ QUAD
- ☐ APEC
- ☐ US Blocks Chinese Firm
- ☐ JAIMEX 2026

पत्र सूचना कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

Social Welfare

'नेचुरोपैथी': स्वस्थ भारत के लिए प्राकृतिक उपचार

देश भर में उपचार, प्रशिक्षण, अनुसंधान और देखभाल

Posted On: 17 NOV 2026 9:58AM

प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) एक दवा-मुक्त और किफायती प्रणाली है जो आहार, उपवास, जल, मिट्टी, मालिश और प्राकृतिक जीवन के माध्यम से शरीर को स्वयं ठीक करने में मदद करती है। भारत 18 नवंबर को 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस' मनाता है, और इसका इस वर्ष का संस्करण 'प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत' विषय के तहत कर्नाटक के नागमंगला में आयोजित किया जाएगा। पुणे स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान 'निसर्ग ग्राम' चलाता है, जो 250 बिस्तरों वाला एक प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है। साथ ही, यह केंद्र सरकार के अंतर्गत 'बेंचमार्क ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज' (बीएनवाईएस) का पहला कॉलेज भी है।

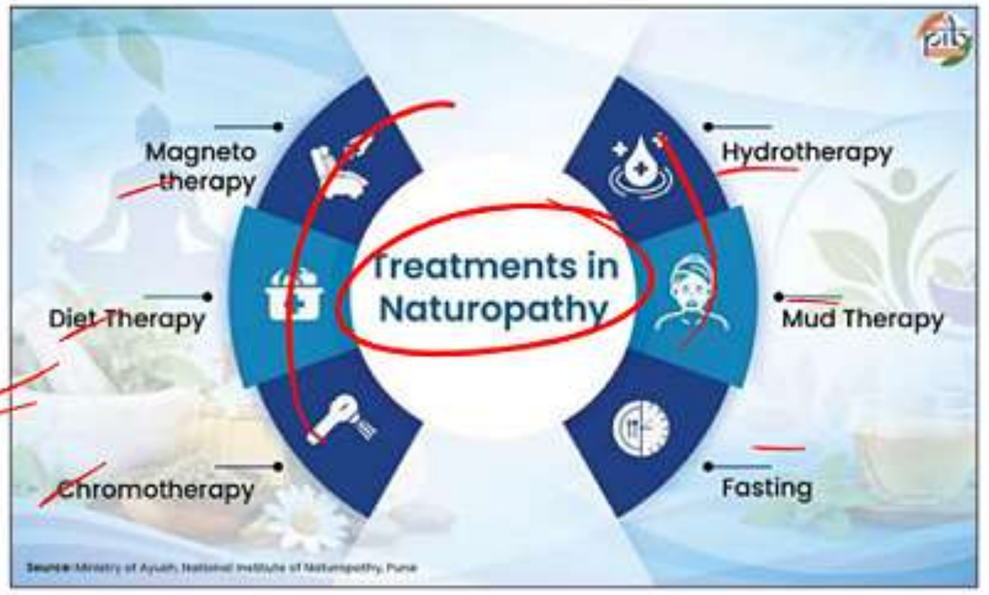
प्रकृति से उपचार

प्राकृतिक चिकित्सा एक सरल विचार पर आधारित है: शरीर में खुद को ठीक करने की ताकत होती है। कई संस्कृतियों की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी यह एक किफायती और दवा-मुक्त प्रणाली है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है। यह प्रकृति के पांच तत्वों—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश—की मदद से शरीर की अपनी जीवन-शक्ति को बढ़ाकर काम करती है।

प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक उपचार की एक पद्धति है और साथ ही जीवन जीने का एक ढंग भी है। यह 'प्रकृति की ओर लौटो' का आह्वान करती है: इसमें सादा खाना और जीवन जीने का तरीका तथा स्वयं, समाज और पर्यावरण के साथ संतुलित जीवन शामिल है। इसमें स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रोगों की रोकथाम, उनका उपचार करने और ठीक होने में मदद करने की क्षमता है।

प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार

- एक प्राकृतिक चिकित्सक (नेचुरोपैथ) प्रकृति की दी हुई चीजों से उपचार करते हैं: जैसे उपवास और आहार, हाइड्रोथेरेपी (पानी से उपचार), मड पैक, कोल्ड पैक, स्नान और मालिश। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के पुणे परिसर, 'निसर्ग ग्राम' में उपचार अनुभागों के अंतर्गत मैग्नेटोथेरेपी (चुंबक से उपचार), क्रोमोथेरेपी (रंग चिकित्सा) और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा, यहां एक योग हॉल और सात्विक आहार केंद्र भी है।



प्राकृतिक चिकित्सा किन रोगों में कारगर है

- प्राकृतिक चिकित्सा को पुरानी बीमारियों, एलर्जी, ऑटोइम्यून, शरीर के अंगों के क्षय से जुड़ी समस्याओं और तनाव से संबंधित विकारों में प्रभावी बताया गया है। पोषण, प्राकृतिक चिकित्सा और जीवनशैली में बदलाव को लेकर इसका महत्व फिर से बढ़ गया है, क्योंकि लोग जीवनशैली से जुड़े विकारों, मोटापे, तनाव और वृद्धावस्था में स्वस्थ जीवन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त आराम और तनाव प्रबंधन सभी उम्र के लोगों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल में सहायक हो सकते हैं।

भारत में प्राकृतिक चिकित्सा और योग

- भारत में प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) योग से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के अनुसार, भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा में योग के साथ-साथ स्वास्थ्य और रोग को समझने की 'पंचभूत' जैसी प्राचीन भारतीय अवधारणाएं भी शामिल हैं। समय के साथ, यह एक संपूर्ण पद्धति के रूप में विकसित हुई है जो रोगों का उपचार और रोकथाम करती है और लोगों को प्रकृति के करीब रहकर स्वस्थ जीवन जीना सिखाती है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी के साथ-साथ, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को भी 'आयुष' प्रणालियों में एक साथ शामिल किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन (2026) में, आयुष मंत्रालय ने दोहराया कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकार ने इस संयोजन के इर्द-गिर्द एक पूरी व्यवस्था तैयार की है: एक ऐसी डिग्री जो प्राकृतिक चिकित्सा को योग विज्ञान के साथ जोड़ती है; दोनों के लिए एक अनुसंधान परिषद - 'सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी' (सीसीआरवाईएन); चिकित्सकों का केंद्रीय पंजीकरण; और देश का पहला राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल।

9वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस: प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत

- 9वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर 2026 को कर्नाटक के नागमंगला स्थित केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईवाईएन) में मनाया जाएगा। इसका विषय 'प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत' है, जो बीमारी से बचाव को प्राथमिकता देता है। इसमें संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, योग और तनाव प्रबंधन पर जोर दिया गया है, साथ ही मोटापे को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह आयोजन प्रधानमंत्री के 'फिट और स्वस्थ भारत' के विजन के अनुरूप है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने कहा:
    - *"'प्राकृतिक चिकित्सा हमें जीवनशैली, प्रकृति और संपूर्ण स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध को समझने के लिए प्रेरित करती है। हमारा जोर विश्वसनीय अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा के साथ जिम्मेदारीपूर्ण एकीकरण के माध्यम से इसके वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने पर है।"*

महात्मा गांधी और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत

- प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, महात्मा गांधी के प्रकृति चिकित्सा के संकल्प को समर्पित है। 18 नवंबर 1945 को, वे पुणे स्थित ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने और उन्होंने इसकी डीड पर हस्ताक्षर किए। आयुष मंत्रालय ने हर साल 'प्राकृतिक चिकित्सा दिवस' मनाने की तारीख की घोषणा की, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई। गांधी जी को भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक माना जाता है। 1946 में, उन्होंने पुणे के पास उरुली कंचन नामक गांव में प्राकृतिक चिकित्सा अभियान का नेतृत्व किया। उसी वर्ष, उन्होंने लिखा:
    - *"मेरा मानना है कि जहां व्यक्तिगत, घरेलू और सार्वजनिक स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, और आहार व व्यायाम के मामले में उचित सावधानी बरती जाती है, वहां बीमारी या रोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जहां पूर्ण आंतरिक और बाहरी पवित्रता हो, वहां बीमारी का होना असंभव है। यदि गांव के लोग इस बात को समझ लें, तो उन्हें डॉक्टरों, हकीमों या वैद्यों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।" (हरिजन, 26 मई 1946)*

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और निसर्ग ग्राम

- पुणे स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) की स्थापना 22 दिसंबर 1986 को हुई। यह उस नेचर क्योर सेंटर में स्थित है, जिसे 17 मार्च 1975 को भारत सरकार को सौंपा गया। इसका मुख्यालय, 'बापू भवन' महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। एनआईएन, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और इसक शासी निकाय के प्रमुख केंद्रीय आयुष मंत्री होते हैं। एनआईएन निम्नलिखित कार्य करता है:
- प्राकृतिक चिकित्सा और योग के क्षेत्र में मौजूदा ज्ञान के मानकीकरण और प्रसार के लिए सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना;
- नेचर क्योर यूनिवर्सिटी की स्थापना करके प्राकृतिक चिकित्सा और योग में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना;
- मानव स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर अनुसंधान करना, सुविधा प्रदान करना और प्रोत्साहित करना; और
- महात्मा गांधी का एक जीवंत स्मारक स्थापित करना।
- एनआईएन सामान्य जरूरतों के लिए विशेष बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) क्लीनिक चलाता है जिसमें प्रसव पूर्व और पश्चात स्वास्थ्य के लिए 'मैटरनल केयर ओपीडी'; आहार, योग और जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से काम करने वाली 'डायबिटीज ओपीडी'; तथा तनाव और चिंता के लिए योग, ध्यान और रिलैक्सेशन के माध्यम से काम करने वाली 'माइंड-बॉडी मेडिसिन ओपीडी' शामिल है।

निसर्ग ग्राम

- 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) के नए परिसर 'निसर्ग ग्राम' का उद्घाटन किया। 25 एकड़ में फैले और 213.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस परिसर में 250 बिस्तरों वाला अस्पताल, अनुसंधान एवं विस्तार सेवा केंद्र तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एक नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज शामिल है। यह देश का पहला राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है, जहां जीवनशैली संबंधी चयापचय (मेटाबॉलिक) विकारों का प्राकृतिक उपचार किया जा सकता है।

निसर्ग ग्राम एक नजर में

परिसर: 25 एकड़, येवलेवाडी, पुणे

लागत: 213.55 करोड़ रुपये

अस्पताल: 250 बिस्तर, पहला राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल

कॉलेज: नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, वर्ष 2026-27 में 100 बीएनवाईएस सीटों के साथ

सुविधाएं: योग हॉल, सात्विक आहार केंद्र, हाइड्रोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी, मालिश और फिजियोथेरेपी।

जनजातीय समुदायों तक पहुंचना

- महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग के सहयोग से, एनआईएन ने पुणे जिले के आंबेगांव तालुका के गोहे (बुद्रुक) में जनजातीय लोगों के लिए 'निसर्ग आरोग्य साधना केंद्र' की स्थापना की है। यह पूरी तरह से सुसज्जित योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है। इस यूनिट में 20 बिस्तर हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग वार्ड हैं, एक योग हॉल है और एक आहार केंद्र है। इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों के माध्यम से समुदाय की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य देखभाल मॉडल प्रदान करना है। यह यूनिट एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करती है, जहां जनजातीय युवा प्राकृतिक चिकित्सा और योग के कौशल सीखते हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए अपनाते हैं। इसके 'उपचार सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम' में हर वर्ष 40 जनजातीय छात्रों के दाखिले की क्षमता है।

- प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने पर जोर देती है। यह बात जनजातीय समुदायों के साथ मेल खाती है; प्रकृति के प्रति उनके ज्ञान और उनके तालमेल को हर साल 'जनजातीय गौरव दिवस' पर मान्यता दी जाती है। यह दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। 16 जनवरी 2026 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर हैदराबाद में जनजातीय चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य इन चिकित्सकों को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सामुदायिक स्तर के साझेदार के रूप में शामिल करना था। मंत्रालय ने एक लाख जनजातीय चिकित्सकों को मान्यता दिलाने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा 2026' के दौरान, 1 और 2 नवंबर को हैदराबाद में एक क्षमता-निर्माण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1,500 पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षण के लिए एक साथ लाया गया।

नेचुरोपैथ्स की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना

- एक विकसित होती हुई प्रणाली को प्रशिक्षित डॉक्टरों की आवश्यकता है और सरकार ने उनके लिए एक स्पष्ट दिशा तय की है।

बीएनवाईएस डिग्री

- एनआईएन देश का पहला केंद्रीय सरकारी संस्थान है जो नई दिल्ली स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, 'श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय' से संबद्ध होकर 'बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज' (बीएनवाईएस) प्रोग्राम चलाता है। बीएनवाईएस का छात्र साढे पांच साल तक परिसर में रहता है: इसमें साढ़े चार साल का शैक्षणिक और नैदानिक प्रशिक्षण होता है, जिसके बाद एक साल की अनिवार्य रोटेटरी रेजिडेंशियल इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'निसर्ग ग्राम' में 100 सीटें उपलब्ध हैं, और कक्षाएं 30 नवंबर 2026 से शुरू होंगी।

- 1 अप्रैल 2024 तक, देश भर में 71 प्राकृतिक चिकित्सा स्नातक कॉलेजों में 5,214 छात्रों की प्रवेश क्षमता थी, जबकि 6 स्नातकोत्तर कॉलेजों में 144 छात्रों की क्षमता थी। 1 जनवरी 2024 तक, 5,083 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सक राज्य बोर्डों और परिषदों में पंजीकृत थे।

केंद्रीय पंजीकरण (सेंट्रल रजिस्ट्रेशन)

- आयुष मंत्रालय के अधीन एनआईएन द्वारा स्थापित नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड (एनआरबी) प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सकों का केंद्रीय पंजीकरण करता है और संस्थानों तथा अस्पतालों को मान्यता देता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के बीएनवाईएस स्नातक इसके केंद्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं।

स्व-देखभाल के लिए पाठ्यक्रम

- एनआईएन अल्प अवधि के कौशल विकास पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा पाक-कला के पाठ्यक्रम मुख्य रूप से स्व-सहायता के लिए होते हैं, ताकि लोग 'स्व-स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता' के ध्येय वाक्य के तहत स्वयं का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मालिश, फिटनेस ट्रेनिंग और योग के पाठ्यक्रम लोगों को पेशेवर रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं।

साक्ष्य आधारित अनुसंधान और नए अस्पताल

- अनुसंधान प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा:
    - *"प्राकृतिक चिकित्सा की विश्वसनीयता को बढ़ाने और इसके व्यापक उपयोग के लिए वैज्ञानिक प्रमाणन आवश्यक है। सीसीआरवाईएन और अन्य संस्थानों के माध्यम से, हम व्यवस्थित अनुसंधान, नैदानिक मूल्यांकन और सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का उचित वैज्ञानिक तरीकों से आकलन किया जा सके और उन्हें जिम्मेदारीपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के तरीकों के रूप में अपनाया जा सके।"*

अनुसंधान परिषद, संस्थान और अस्पताल

- आयुष मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित ' केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (सीसीआरवाईएन) वर्ष 1978 से योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान, प्रचार-प्रसार और विकास कार्य कर रही है। भारत भर में इस परिषद की 22 इकाइयां हैं। मंत्रालय की पांच अनुसंधान परिषदों ने मिलकर वर्ष 2025-26 के दौरान 653 शोध पत्र प्रकाशित किए।

- भारत में अब हरियाणा के झज्जर और कर्नाटक के नागमंगला में 200 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल हैं। इसके साथ ही, यहां योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्नातकोत्तर संस्थान भी हैं। झज्जर स्थित सीआरआईवाईएन, जो 19 एकड़ में 63.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक शीर्ष अनुसंधान और शिक्षा सुविधा है, का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी 2024 को किया था—उसी दिन 'निसर्ग ग्राम' का भी उद्घाटन किया गया था। 2024 में, प्रधानमंत्री ने ओडिशा के खोरदा व छत्तीसगढ़ के रायपुर में दो और सीआरआईवाईएन का शिलान्यास भी किया। 1 अप्रैल 2024 तक, देश भर के 35 अस्पतालों (जिनमें कुल 1,663 बिस्तर हैं) और 95 औषधालयों में प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

- राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) में एक समर्पित अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी भी है। यह अनुसंधान पद्धति कार्यशालाएं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस ट्रेनिंग, अवलोकन अध्ययन, व्यवस्थित समीक्षा और सहयोगात्मक अनुसंधान का संचालन करती है। इसके मौजूदा इन-हाउस अध्ययनों में उपवास के विभिन्न तरीकों, हिप बाथ और वेट शीट पैक, टाइप 2 मधुमेह पर धूप के प्रभाव, एक एकीकृत प्राकृतिक चिकित्सा व योग कार्यक्रम और गट माइक्रोबायोटा (आंत में रहने वाले सूक्ष्मजीव) पर इसके प्रभाव, और घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग जैसे विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारत की पारंपरिक पद्धतियों और विश्व

- भारत में विदेशों से आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी मरीजों की संख्या 2020 के 1,82,945 से बढ़कर 2024 में 6,44,387 हो गई है, जिसमें योग, आयुर्वेद और वेलनेस-आधारित चिकित्सा पद्धतियों का बड़ा योगदान है। विदेशी मरीज अब पुरानी बीमारियों, जीवनशैली संबंधी विकारों, पुनर्वास और वेलनेस कार्यक्रमों के लिए भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों—जैसे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी—को तेजी से अपना रहे हैं।
- भारत का वेलनेस टूरिज्म योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जैसी पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से निवारक और संपूर्ण स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ऐसी स्वास्थ्य-देखभाल तक पहुंच आसान बनाने के लिए, सरकार ने 27 जुलाई 2023 को विदेशी नागरिकों और उनके अटेंडेंट के लिए एक खास आयुष वीज़ा शुरू किया, जो आयुष प्रणाली के तहत इलाज करवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2022 में गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में इस वीज़ा की घोषणा की थी। यह भारत की हील इन इंडिया पहल के रोडमैप का हिस्सा है, जो भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के एक गंतव्य-देश के रूप में बढ़ावा देती है। फरवरी 2026 के केंद्रीय बजट में घोषित पांच प्रस्तावित 'रीजनल मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब' में आयुष केंद्र भी शामिल होंगे। इन केंद्रों में आधुनिक चिकित्सा उपचार के साथ-साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां, वेलनेस सेवाएं और पुनर्वास सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होंगी।

प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा

- प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) सरल तरीकों- अच्छा भोजन, आराम, शारीरिक गतिविधि और प्रकृति की उपचार शक्ति- पर आधारित है। भारत ने इस पद्धति को एक राष्ट्रीय संस्थान और पहला राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल दिया है। इसके अलावा, यहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री, अनुसंधान संस्थान और अस्पताल, केंद्रीय पंजीकरण, और देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में 'आयुष' देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध है। 18 नवंबर 2026 को नागमंगला में 9वें राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर, 'प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत' के विजन के तहत हर आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, योग और स्वस्थ जीवन पर जोर दिया जाएगा।

📌 प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: नेचुरोपैथी' (प्राकृतिक चिकित्सा) और 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्राकृतिक चिकित्सा एक दवा-मुक्त और किफायती प्रणाली है जो आहार, उपवास, जल, मिट्टी और मालिश के माध्यम से शरीर को स्वतः ठीक करने में मदद करती है.
2. भारत में प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस' मनाया जाता है.
3. प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के पांच तत्वों—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश—की मदद से शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाकर काम करती है.

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Youtube Homework
↳ Youtube पे Comment 30+
↳ Answer

📌 मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न:** "आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों और बढ़ती चिकित्सा लागत के दौर में, 'प्राकृतिक चिकित्सा' (नेचुरोपैथी) जैसी दवा-मुक्त प्रणालियाँ निवारक स्वास्थ्य देखभाल (Preventive Healthcare) में क्या भूमिका निभा सकती हैं? विश्लेषण कीजिए।" *(उत्तर 150 से 200 शब्दों में दें)*

The battle for responsible microfinance

Is the RBI drawing a necessary line between financial inclusion and reckless lending? Is the microfinance industry prioritising loan growth over borrower protection? Are existing credit checks enough to assess a household's actual repayment capacity? Is pseudo-consent becoming a wider banking-sector concern?

EXPLAINER

Santosh Y. Perumal

The story so far:

The firm stand of the Reserve Bank of India (RBI) on the microfinance industry has sent out strong messages that financial inclusion cannot be at the cost of household over-indebtedness, and responsible lending begins even before a loan is sanctioned. After two years of contraction, stability appears to have returned in the country's microfinance sector – which primarily targets unbanked or under-banked individuals, informal workers, and rural households living below or near the poverty line – but recovery remains fragile.

Industry-wide early-stage delinquency (30-179 days past due) fell to 1.9% in June 2026 from 6.1% a year earlier. However, loans overdue by more than 180 days were high at 17.4%, implying the extent of legacy stress.

What is microfinance's footprint?

The SIDBI Equifax Microfinance Pulse Report, covering June 2026, shows that the outstanding microfinance portfolio fell 12% year-on-year (YoY) to ₹2.69 lakh crore. The sector had 7.15 crore active loan accounts. Disbursements during April-June 2026 however grew 17% YoY to ₹62,302 crore.

The Sa-Dhan Quarterly Microfinance report gives a somewhat broader picture, with the industry's outstanding portfolio at ₹3.26 lakh crore in June 2026, down 7.6% YoY. Banks' direct microfinance portfolio was about ₹83,080 crore in June 2026, accounting for one-fourth of the industry's portfolio, according to Microfinance Institutions Network (MFIN) data, it represented less than 0.4% of total scheduled commercial bank credit.

Direct financial footprint is relatively small, but microfinance's influence on rural consumption, women's entrepreneurship, informal businesses and household livelihoods is substantial. The sector's cumulative contribution to India's Gross Value Added (GVA) was 2.03% in 2018-19, projected to rise to 2.7% by 2025-26.



RBI Deputy Governor emphasised that lenders must provide the Key Facts Statement regarding loans and obtain an acknowledgement that the borrower understands the commitment. GETTY IMAGES

What are the industry demands?

One of the key demands is an upward revision of the ₹3 lakh annual household income threshold, which was introduced in 2022. According to the MFIN, the threshold does not adequately reflect increases in wages, household incomes and inflation. Consequently, borrowers whose incomes improved marginally may be out of the regulatory definition, although they may continue to require small ticket credit.

Another demand is on the 50% fixed-obligation-to-income ratio (FOIR) as the industry seeks a rational review from the banking regulator as they view that a uniform 50% repayment ceiling may not adequately capture regional differences in household income, consumption expenditure, cost of living and repayment capacity.

Divergence over FOIR, income eligibility and lending practices could create uncertainty and discourage fresh capital in the sector. It could also push financially vulnerable households towards informal moneylenders, potentially exposing them to higher interest rates. The microfinance industry wants certain repayment obligations to be assessed more flexibly, including proposals to consider only the interest component of some loans rather than the entire principal and interest repayment.

What did the RBI say?

On FOIR, the RBI instead viewed excluding principal repayments as understating actual household indebtedness. In this regard, it cites a study that showed an average microfinance borrower spends just 18.7% of her monthly household income on loan repayment, while about two-thirds goes towards consumption.

On the threshold, the RBI's sights are on industry developments, hinting that regulatory flexibility will depend on demonstrable improvements in household income assessment, credit reporting and responsible lending. "It is imperative for the industry to strengthen its lending practices, uphold responsible credit standards and build greater resilience to withstand emerging challenges," RBI Deputy Governor Shirish Chandra Murmu had said.

For the RBI, it is a tight-rope walk, balancing the financial inclusion and due diligence. It has to ensure that tighter credit discipline does not become a barrier to financial inclusion. At the same time, it shouldn't undermine the purpose of microfinance.

What is pseudo-consent?

Highlighting possible instances in which borrowers sign documents without adequate information about what they contain, Mr Murmu distinguished between mindful consent and pseudo-consent. He emphasised that lenders must provide the Key Facts Statement (KFS), explain its contents in a language understood by the borrower and obtain an acknowledgement that the borrower understands the commitment.

With expanding digital lending, instant personal loans, credit cards and other retail products, pseudo-consent could become a wider banking sector problem.

Elevated crude oil prices, costlier transportation and high inflation in essential commodities, can squeeze household disposable incomes, which translate into additional borrowings. In such a scenario, financial inclusion could inadvertently deepen household indebtedness, turning credit into a source of financial distress.

Is there a conflict of interest?

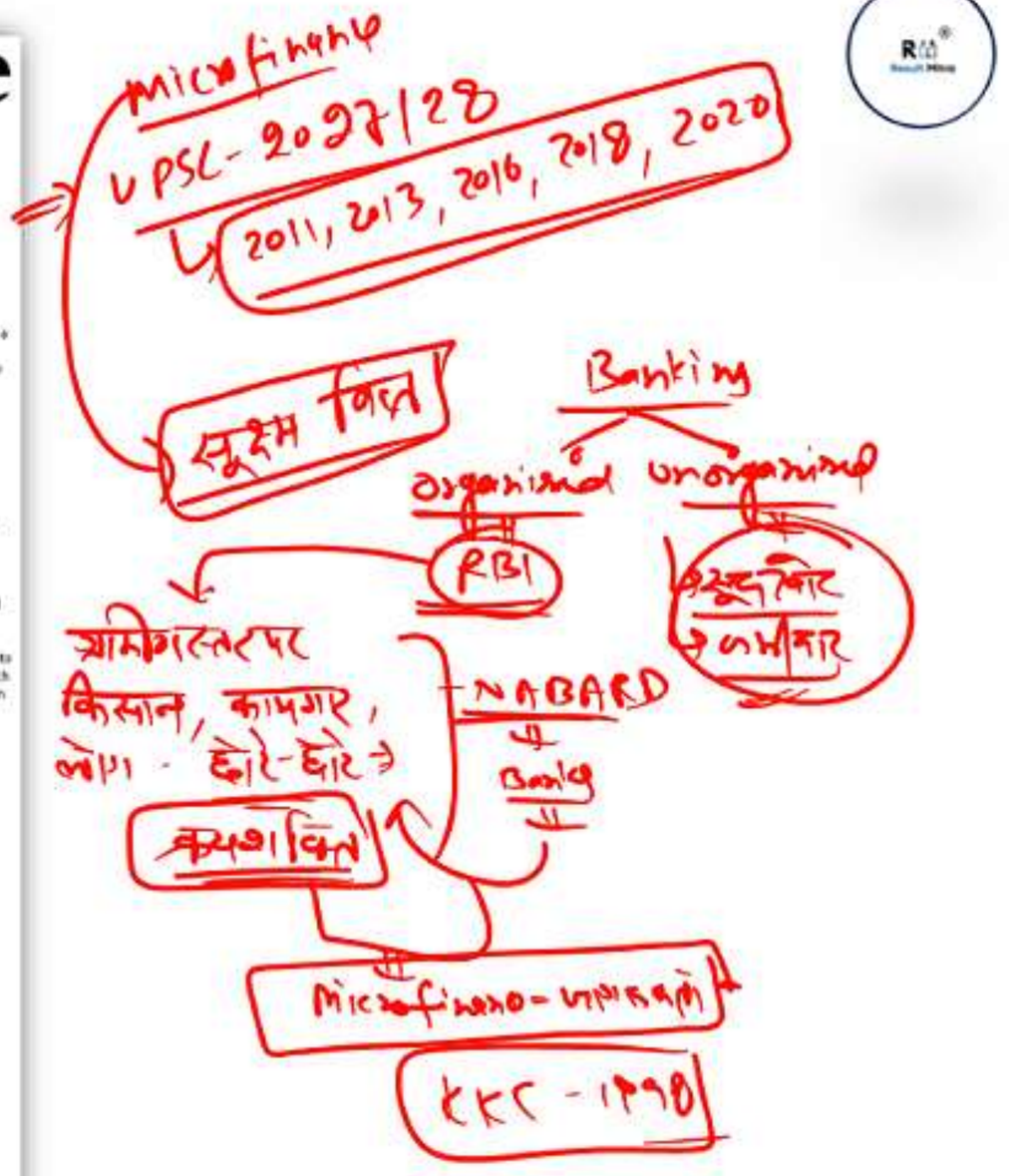
The two RBI-recognised SROs or Self-Regulatory Organisations – MFIN and Sa-Dhan – are industry associations whose members are also the institutions they are expected to monitor. MFIs may market additional financial products such as insurance, savings-linked products and other services alongside microcredit, creating a potential conflict between the borrower's actual financial needs and the institution's revenue-generating interests.

What is the underlying ethos?

The RBI's June 2026 directions on advertising, marketing and sale of financial products seek to prohibit deceptive practices and ensure explicit customer consent. These requirements are scheduled to take effect from January 1, 2027.

THE GIST

- The RBI's firm stand on the microfinance industry sends a message that financial inclusion cannot come at the cost of household over-indebtedness
- The microfinance industry wants certain repayment obligations to be assessed more flexibly, including by considering only the interest component of some loans
- Elevated crude oil prices and inflation in essential commodities can squeeze household incomes, leading to additional borrowings. In such a scenario, financial inclusion could inadvertently deepen household indebtedness



जिम्मेदार माइक्रोक्रेडिट (सूक्ष्म वित्त) के लिए संघर्ष

- **प्रस्तावना प्रश्न:** क्या आरबीआई (RBI) वित्तीय समावेशन और अंधाधुंध ऋण देने (reckless lending) के बीच एक आवश्यक रेखा खींच रहा है? क्या सूक्ष्म वित्त उद्योग (microfinance industry) कर्जदार की सुरक्षा की तुलना में ऋण वृद्धि को अधिक प्राथमिकता दे रहा है? क्या किसी परिवार की वास्तविक चुकौती क्षमता का आकलन करने के लिए मौजूदा क्रेडिट जाँच पर्याप्त हैं? क्या छद्म-सहमति (pseudo-consent) बैंकिंग क्षेत्र की एक बड़ी चिंता बनती जा रही है?

अब तक की स्थिति (The story so far):

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कड़ा रुख सूक्ष्म वित्त उद्योग को यह स्पष्ट संदेश भेजता है कि वित्तीय समावेशन (financial inclusion) किसी भी कीमत पर घरेलू अति-ऋणग्रस्तता (household over-indebtedness) की कीमत पर नहीं हो सकता, और ऋण स्वीकृत होने से पहले ही जिम्मेदार ऋण देना जरूरी है।
- दो साल के संकुचन (contraction) और स्थिरता के बाद, देश के सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखे हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बिना बैंक खाते वाले या कम बैंकिंग सुविधा वाले व्यक्ति, अनौपचारिक श्रमिक और वे ग्रामीण परिवार शामिल हैं जो गरीबी रेखा से नीचे या उसके करीब जीवन बसर करते हैं, लेकिन यहाँ रिकवरी अभी भी नाजुक बनी हुई है।
- उद्योग स्तर पर शुरुआती चरण की चूक (30-179 दिन बकाया) जून 2026 में घटकर 1.9% रह गई, जो एक साल पहले 6.1% थी। हालांकि, 180 दिनों से अधिक समय से बकाया ऋण अभी भी 17.4% पर थे, जो पुराने वित्तीय संकट (legacy stress) के स्तर को दर्शाते हैं।

सूक्ष्म वित्त का दायरा क्या है? (What is microfinance's footprint?)

- **SIDBI-Equifax माइक्रोक्रेडिट पल्स रिपोर्ट (जून 2026 के अनुसार):** कुल बकाया सूक्ष्म वित्त पोर्टफोलियो साल-दर-साल (YoY) आधार पर 12% गिरकर ₹2.69 लाख करोड़ हो गया। इस क्षेत्र में 7.15 करोड़ सक्रिय ऋण खाते हैं। हालाँकि, अप्रैल-जून 2026 के दौरान संवितरण (disbursements) साल-दर-साल 17% बढ़कर ₹62,302 करोड़ हो गया।
- **Sa-Dhan त्रैमासिक रिपोर्ट:** यह कुछ बेहतर तस्वीर दिखाती है, जिसके अनुसार जून 2026 में उद्योग का कुल बकाया पोर्टफोलियो ₹3.26 लाख करोड़ था, जो साल-दर-साल 7.6% कम है। जून 2026 में बैंकों का प्रत्यक्ष (direct) सूक्ष्म वित्त पोर्टफोलियो ₹83,080 करोड़ था, जो उद्योग के पोर्टफोलियो का एक चौथाई हिस्सा है। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) के आंकड़ों के अनुसार, यह कुल वाणिज्यिक बैंक ऋण का 0.4% से भी कम था।
- प्रत्यक्ष वित्तीय पदचिह्न अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन ग्रामीण उपभोग, महिला उद्यमिता, अनौपचारिक व्यवसायों और घरेलू आजीविका पर सूक्ष्म वित्त का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है।

उद्योग की मांगें क्या हैं? (What are the industry demands?)

- **आय सीमा में संशोधन:** एक मुख्य मांग 2022 में शुरू की गई ₹3 लाख की वार्षिक घरेलू आय सीमा को ऊपर की ओर संशोधित (upward revision) करने की है। MFIN के अनुसार, यह सीमा मजदूरी, घरेलू आय और मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि को ठीक से नहीं दर्शाती है। नतीजतन, जिन परिवारों की आय थोड़ी सुधर गई है, वे विनियामक परिभाषा से बाहर हो सकते हैं, हालांकि उन्हें अभी भी छोटे आकार के ऋण की आवश्यकता हो सकती है।
- **FOIR पर ढील:** दूसरी मांग **निश्चित-बाध्यता-से-आय अनुपात (FOIR - fixed-obligation-to-income ratio)** पर है। उद्योग इसे एक तर्कसंगत समीक्षा के रूप में देखता है क्योंकि बैंकिंग नियामक का मानना है कि 50% की एकसमान चुकौती सीमा (repayment ceiling) घरेलू आय, उपभोग व्यय, जीवन लागत और चुकौती क्षमता में क्षेत्रीय अंतर को पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं करती है।

आरबीआई ने क्या कहा? (What did the RBI say?)

- **FOIR पर:** आरबीआई ने मूलधन के पुनर्भुगतान को बाहर करने के बजाय घरेलू स्तर पर वास्तविक ऋणग्रस्तता को कम आंकने के रूप में देखा। इस संबंध में, इसने एक अध्ययन का हवाला दिया जिसमें दिखाया गया कि एक औसत माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ता अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7% ऋण चुकौती पर खर्च करता है, जबकि लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपभोग की ओर जाता है।
- इस सीमा पर, उद्योग के घटनाक्रमों पर आरबीआई की कड़ी नजर है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विनियामक लचीलापन (regulatory flexibility) घरेलू आय आकलन, क्रेडिट रिपोर्टिंग और जिम्मेदार ऋण देने में सराहनीय सुधारों पर निर्भर करेगा। आरबीआई डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा, *"उद्योग के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी ऋण देने की प्रथाओं को मजबूत करे, क्रेडिट मानकों को बरकरार रखे और उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक लचीलापन बनाए।"*
- आरबीआई के लिए यह एक कछुए की चाल जैसा संतुलन है—उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सख्त क्रेडिट अनुशासन वित्तीय समावेशन में बाधा न बने, साथ ही यह सूक्ष्म वित्त के उद्देश्य को भी कमजोर न करे।

छद्म-सहमति क्या है? (What is pseudo-consent?)

- उन संभावित मामलों को उजागर करते हुए जिनमें उधारकर्ता बिना यह जाने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं कि उनमें क्या शामिल है, श्री मुर्मू ने **सच्ची सहमति (mindful consent)** और **छद्म-सहमति (pseudo-consent)** के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऋणदाताओं को **मुख्य तथ्य विवरण (KFS - Key Facts Statement)** प्रदान करना चाहिए, इसके contenuti को उस भाषा में समझाना चाहिए जिसे उधारकर्ता समझ सके, और इस बात की पावती (acknowledgement) प्राप्त करनी चाहिए कि उधारकर्ता ने अपनी प्रतिबद्धता को समझ लिया है।
- डिजिटल ऋण (digital lending) के विस्तार, तत्काल व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और अन्य खुदरा उत्पादों के साथ, छद्म-सहमति बैंकिंग क्षेत्र की एक बड़ी समस्या बन सकती है।
- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, परिवहन की अधिक लागत और आवश्यक वस्तुओं में उच्च मुद्रास्फीति घरेलू प्रयोज्य आय (disposable income) को निचोड़ सकती है, जिससे अतिरिक्त उधार लेना पड़ सकता है। ऐसे में, वित्तीय समावेशन अनजाने में घरेलू अति-ऋणग्रस्तता को गहरा कर सकता है, जिससे क्रेडिट वित्तीय संकट का स्रोत बन सकता है।

क्या हितों का टकराव है? (Is there a conflict of interest?)

- आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त दो SRO (स्व-नियामक संगठन) — **MFIN** और **Sa-Dhan** — ऐसे उद्योग संघ हैं जिनके सदस्य वे संस्थान भी हैं जिनकी निगरानी करने की उनसे अपेक्षा की जाती है। MFI माइक्रोक्रेडिट के साथ-साथ बीमा, बचत-लिंक्ड उत्पाद और अन्य सेवाएं जैसे अतिरिक्त वित्तीय उत्पाद बेच सकते हैं, जिससे उधारकर्ता की वास्तविक वित्तीय जरूरतों और संस्थान के लाभ पैदा करने वाले हितों के बीच संभावित हितों का टकराव पैदा हो सकता है।

अंतर्निहित लोकाचार क्या है? (What is the underlying ethos?)

- विज्ञापन, विपणन और वित्तीय उत्पादों की बिक्री पर आरबीआई के जून 2026 के निर्देश भ्रामक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने और स्पष्ट ग्राहक सहमति सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। ये आवश्यकताएं **1 जनवरी, 2027** से लागू होने वाली हैं।

मुख्य सार (THE GIST)

- आरबीआई का कड़ा रुख सूक्ष्म वित्त उद्योग को यह संदेश देता है कि वित्तीय समावेशन कभी भी घरेलू अति-ऋणग्रस्तता की कीमत पर नहीं आ सकता।
- सूक्ष्म वित्त उद्योग कुछ ऋणों के केवल मूलधन और ब्याज के बजाय केवल ब्याज घटक पर विचार करके चुकौती दायित्वों का अधिक लचीले ढंग से आकलन चाहता है।
- कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति घरेलू आय को प्रभावित कर सकती है, जिससे अतिरिक्त ऋण लेना पड़ सकता है; ऐसे में वित्तीय समावेशन अनजाने में घरेलू ऋणग्रस्तता को बढ़ा सकता है।

1. UPSC Prelims 2013

- **प्रश्न: 'सूक्ष्म वित्त' (Microfinance) के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:**

1. सूक्ष्म ऋण (Micro-credit)
2. सूक्ष्म बचत (Micro-savings)
3. सूक्ष्म बीमा (Micro-insurance)
4. धन अंतरण (Fund transfer)

उपर्युक्त में से कौन-सी सेवाएँ सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं?

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

2. UPSC Prelims 2011

- **प्रश्न: सूक्ष्म वित्त (Microfinance), कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाओं का प्रावधान है, जिसमें उपभोक्ता और स्व-नियोजित दोनों शामिल हैं। सूक्ष्म वित्त के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवा(ओं) में निम्नलिखित में से कौन-सी शामिल है/हैं?**

1. ऋण सुविधाएँ (Credit facilities)
2. बचत सुविधाएँ (Savings facilities)
3. बीमा सुविधाएँ (Insurance facilities)
4. निधि अंतरण सुविधाएँ (Fund transfer facilities)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

3. UPSC Prelims 2016

प्रश्न: 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (Pradhan Mantri MUDRA Yojana) का उद्देश्य क्या है?

- (a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
- (b) निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराना
- (c) वृद्ध एवं निराश्रित व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना
- (d) कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को निधि प्रदान करना

4. UPSC Prelims 2023

प्रश्न: 'स्व-सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्व-सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम भारत में नाबार्ड (NABARD) द्वारा प्रारंभ किया गया था।
2. एक एसएचजी (SHG) में, सभी सदस्य ऋण के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं जो बैंक व्यक्तिगत सदस्य को देता है।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी को सहायता प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारतीय सूक्ष्म वित्त (Microfinance) क्षेत्र और इससे संबंधित विनियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सिडबी-इक्विफाइक्स माइक्रोक्रेडिट पल्स रिपोर्ट (जून 2026) के अनुसार, कुल बकाया सूक्ष्म वित्त पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है।
2. सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में मुख्य रूप से बिना बैंक खाते वाले या कम बैंकिंग सुविधा वाले व्यक्ति, अनौपचारिक श्रमिक और ग्रामीण परिवार शामिल हैं।
3. MFIN और Sa-Dhan, आरबीआई (RBI) द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठन (SRO) हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains) अभ्यास प्रश्न

- **प्रश्न:** "वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और जिम्मेदार ऋण देने (Responsible Lending) के बीच संतुलन बनाना वर्तमान सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है।" इस कथन के आलोक में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के समक्ष मौजूद वर्तमान चिंताओं (जैसे अति-ऋणग्रस्तता और छद्म-सहमति) का परीक्षण कीजिए तथा क्षेत्र को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। *(उत्तर 200 से 250 शब्दों में दें)*

Transgender rights, healthcare should not be compromised

Anand Zachariah

Sudharshini Subramaniam

Swati Jayant Pawar

L. Ramakrishnan

Gargi Dhananjayan

C. Meena

K.S. Jacob

Authors are physicians, public health practitioners and activists working to advance LGBTQIA+ health and rights, and promote greater equality, inclusion and social justice for transgender persons

Parliament passed the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 earlier this year. The new Act represents a significant shift from the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. The 2026 amendment removes the principle of self identification and demands a medical board's recommendation; a selection from prescribed categories; and certification by a District Magistrate. It fundamentally changes legal recognition for transgender persons from self identification to medical assessment. While the 2026 Act does increase protection, it changes the philosophical foundation of transgender rights – from recognition based substantially on autonomy and self-identification towards recognition mediated by medical and administrative authorities.

Creating medico-legal hurdles

The definition of "transgender" as introduced in the Amendment Act is in contradiction to established international evidence and guidelines laid down in the World Health Organization ICD-11 and the World Professional Association for Transgender Health Standards of Care Version 8.

The new Act conflates two different issues: whether a person's gender identity is legally valid and a person's eligibility for social welfare benefits. It also makes a medical authority the gatekeeper of gender identity. The Supreme Court had held that gender identity is part of one's personal autonomy and dignity under Article 21, and had rejected the idea that gender identity should be dependent on medical intervention. This new definition resurrects the discredited psychiatric model in which a deeply felt internal and social identity becomes a matter for professional certification.

It raises the broader question of whether the law is protecting transgender persons or deciding which transgender identities are sufficiently medically recognisable to deserve protection. The new amendment defines 'transgender' very narrowly – it removes trans men, trans women and genderqueer persons from its statutory definition and introduces a restricted set of categories, which include certain socio-cultural identities and persons with specified variations in sex characteristics. For transgender persons excluded from this definition, it would create a mismatch between the gender incongruence experienced by the individual and that recognised administratively. It also excludes people who previously fell within the protection of the 2019 Act by medicalising some identities and culturally recognising some others (identities such as *kinner*, *hijra*, *aravani*, *jogta*, eunuch). It mandates medical certification of even such cultural categories. While the medical board can recognise biological characteristics (which may or may not co-occur with a transgender identity), how will it determine membership within a socio-cultural community? The new Act does not provide an effective appeal mechanism nor independent review.

The *NALSA* judgment strongly articulated a rights and autonomy approach while the 2026 Act supports a paternalistic model with reduced autonomy. Should the state protect a marginalised group by introducing medico legal hurdles or by maximising individual autonomy while providing strong protections against exploitation? The Act creates potential tensions with the constitutional reasoning of *NALSA*, risks excluding many gender-diverse people, and leaves important procedural questions about certification and appeal unresolved.

The consequences

The new Act has many negative public health consequences. The lack of an appeal process is particularly important as the certificate has implications for access to statutory rights and entitlements. It introduces multiple barriers to gender affirming care, documentation, employment, education, social-security schemes, insurance and mental health services. The ambiguity regarding the legality of gender-affirming and supportive care has resulted in uncertainty among care providers and has led some of them to delay, suspend, or withdraw services. This is likely to drive individuals toward unregulated and informal sources of care, including private, unqualified providers operating outside established medical systems. The shift towards the "grey market" for hormones and surgical interventions may increase the risk of self-medication, post-operative complications, infections, side-effects and morbidity. The bureaucratic requirements may lead to significant out-of-pocket expenditures and delays in accessing care. There is also emerging field-level evidence from helplines, community consultations, and hearing sessions indicating an increase in distress calls from transgender individuals, including reports of suicidal ideation, depression, sleep disturbance, and anxiety following the introduction of the amendment.

India has come a long way in recognising the rights of transgender persons. The 2014 *NALSA* judgment recognised transgender persons' right to identity and dignity, and the Government has since introduced laws, welfare schemes, identity certificates, shelter homes, insurance and healthcare initiatives for the community. And yet, transgender people and communities face massive discrimination in nearly all sectors. The National Human Rights Commission's (NHRC) 2026 advisory identifies continuing concerns involving education, healthcare, property and inheritance, employment, documentation, and policing and grievance redressal. The Act goes against the NHRC's recommendations particularly with respect to self-identification, independent grievance mechanisms and reducing documentation barriers.

Transgender healthcare

Many transgender persons hesitate to enter hospitals because of previous experiences, fear of being judged, lack of understanding among healthcare workers, concerns about privacy, cost, or dignified care. These become powerful barriers to seeking healthcare for people who have faced discrimination in environments that cater to cisgender people.

Some hospitals have dedicated transgender clinics that provide specialised care, counselling, hormone therapy, and gender-affirming services. Nevertheless, transgender persons can develop other illnesses such as diabetes or hypertension and may need the full range of care – primary, preventative, emergency, specialist, surgery, dental etc. They should not have to search for a "transgender-inclusive hospital" every time they fall sick. Transgender healthcare should become part of general healthcare.

Clinical understanding of the care needs of a transgender person remains rudimentary in India. Doctors, nurses, receptionists, security staff and hospital administrators need to be trained in basic transgender health. While the Madras High Court's *Sushma* (2021) verdict mandates such education, curriculum changes proposed by the National Medical Commission have failed to incorporate such training. Hospital forms and records should allow appropriate recording of a patient's preferred name and gender identity while retaining clinically relevant information. A mandate of the 2019 Act to designate a Complaints Officer in every establishment has not been complied with in most hospitals. There is an urgent need for inclusive mainstream healthcare, supported by specialised services when necessary.

The passage of the 2026 Act is contributing to a public health emergency. India should focus on the humanity of all people rather than divide them on the basis of bigotry and prejudice. One's humanity should be judged by the people we include rather than by those we exclude.

Clinical understanding of the care needs of a transgender person remains rudimentary in India. Doctors, nurses and hospital administrators need to be trained in basic transgender health

→ LGBTQ+
↳ Transgender

ट्रांसजेंडर अधिकार, स्वास्थ्य सेवा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए

- **लेखकगण:** आनंद ज़कारिया, सुदर्शनी सुब्रामनियन, स्वाति जयंत पवार, एल. रामकृष्णन, गार्गी धनंजय, सी. मीना, और के.एस. जैकोब (ये सभी चिकित्सक, सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर और कार्यकर्ता हैं जो LGBTQIA+ स्वास्थ्य, अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं)।

मुख्य अंश और सारांश (Summary of the Article):

- **नया संशोधन अधिनियम, 2026:** इस साल की शुरुआत में संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन अधिनियम पारित किया। यह नया अधिनियम 2019 के मूल अधिनियम से एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, क्योंकि यह 'स्वयं-पहचान' (self-identification) के सिद्धांत को हटाकर मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, निर्धारित श्रेणियों में से चयन और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन की मांग करता है। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कानूनी मान्यता के आधार को व्यक्तिगत स्वायत्तता से हटाकर चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में ले आता है।

चिकित्सकीय-कानूनी बाधाएं पैदा करना:

- संशोधन अधिनियम में "ट्रांसजेंडर" की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ICD-11 और वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (WPATH) के दिशा-निर्देशों के विपरीत है।
- यह अधिनियम दो अलग-अलग मुद्दों—पहला, किसी की लिंग पहचान कानूनी रूप से मान्य है या नहीं, और दूसरा, सामाजिक कल्याण लाभों के लिए व्यक्ति की पात्रता—को आपस में मिला देता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि लिंग पहचान अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा का हिस्सा है। यह नया संशोधन एक पुराने, खारिज किए जा चुके मनोचिकित्सकीय मॉडल को पुनर्जीवित करता है।
- यह अधिनियम 'ट्रांसमेन', 'ट्रांसवुमन' और 'जेंडरक्वीर' व्यक्तियों को इसकी वैधानिक परिभाषा से बाहर करता है, जिससे व्यक्तियों की आंतरिक पहचान और प्रशासनिक रूप से मान्यता प्राप्त पहचान के बीच बेमेल स्थिति पैदा होती है।

कानून के परिणाम (The consequences):

- अपील प्रक्रिया का अभाव: अधिनियम में अपील की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं दी गई है, जो कि सांविधिक अधिकारों और हकदारियों तक पहुँच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह संशोधन लिंग-पुष्टि देखभाल (gender-affirming care), दस्तावेज़ीकरण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में कई बाधाएँ खड़ी करता है।
- देखभाल करने वाले कुछ प्रदाताओं में अनिश्चितता पैदा हो गई है, जिससे वे अपनी सेवाएँ देने में देरी कर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। इसके कारण लोग अनियंत्रित और अनौपचारिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के पास जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे आत्म-चिकित्सा (self-medication), संक्रमण और रुग्णता का जोखिम बढ़ जाता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 2026 के परामर्श में भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और शिकायत निवारण से जुड़ी चिंताओं को उठाया गया है।

ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा (Transgender healthcare):

- कई ट्रांसजेंडर लोग पिछले अनुभवों, पूर्वाग्रहों और स्वास्थ्य कर्मियों में समझ की कमी के कारण अस्पतालों में जाने से हिचकिचाते हैं।
- हालांकि कुछ अस्पतालों में विशेष क्लीनिक हैं, लेकिन ट्रांस व्यक्तियों को मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी अन्य बीमारियाँ भी हो सकती हैं। उन्हें प्राथमिक, निवारक और आपातकालीन सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ मिलनी चाहिए। हर बार बीमार पड़ने पर उन्हें "ट्रांसजेंडर-समावेशी अस्पताल" की तलाश नहीं करनी चाहिए।
- भारत में डॉक्टरों, नर्सों, रिसेप्शनिस्टों और अस्पताल प्रशासकों को बुनियादी ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य देखभाल में प्रशिक्षित किए जाने की सख्त आवश्यकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के 'सुषमा (2021)' फैसले में ऐसे प्रशिक्षण का आदेश दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम इसे शामिल करने में विफल रहे हैं।
- अस्पतालों के फॉर्म और रिकॉर्ड्स में मरीज के पसंदीदा नाम और लिंग पहचान को दर्ज करने की अनुमति होनी चाहिए, जबकि चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक जानकारी सुरक्षित रहे।

- **निष्कर्ष:** 2026 के इस संशोधन अधिनियम का पारित होना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में योगदान दे रहा है। भारत को लोगों को कट्टरता और पूर्वाग्रह के आधार पर बांटने के बजाय सभी इंसानों की मानवता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुख्य सार (THE GIST)

- 2026 का नया संशोधन अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को 'स्वयं-पहचान' से हटाकर मेडिकल बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाणन पर निर्भर बनाता है।
- यह बदलाव कानूनी पहचान को जटिल बनाता है और स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में गंभीर बाधाएँ पैदा करता है।
- भारत के अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रांसजेंडर-संवेदनशील देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे बिना किसी भेदभाव के सभी को स्वास्थ्य सेवाएँ दे सकें।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

- **प्रश्न: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों, विधिक मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 द्वारा स्थापित विधिक ढांचा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ICD-11 और 'वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ' (WPATH) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 के तहत लिंग पहचान की प्रक्रिया को 'स्वयं-पहचान' (self-identification) से हटाकर एक चिकित्सा और प्रशासनिक अनुमोदन तंत्र (मेडिकल बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट प्रमाणन) के अधीन कर दिया गया है।
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 2026 के परामर्श में शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्षेत्रों में बने हुए भेदभावपूर्ण अवरोधों को रेखांकित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains)

- *"स्व-अभिनिर्धारण (self-identity) से सम्बन्धित निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में भली-भाँति संरक्षित है। इस संदर्भ में, उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में 2026 के संशोधन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।"*

महत्वपूर्ण तथ्य

ECI- SIR

YouTube Homework

Nearly 75 lakh more names added to draft SSR rolls in 13 States, U.T.s

Sreeparna Chakrabarty
NEW DELHI

Months after final voter lists were published following the contentious special intensive revision (SIR) of electoral rolls, nearly 75 lakh more names have been added in draft voter lists published in 13 States and Union Territories via a special summary revision (SSR) process.

The combined size of the electorate in these States before the SIR was 49.61 crore, which shrunk to 45.22 crore after the SIR and has now increased to 45.96 crore in the draft SSR list. This means there has been a cumulative increase of 1.64%.

Uttar Pradesh, which published its draft SSR list on Tuesday, saw 18.84 lakh names being added to its voter lists, the largest in absolute numbers so far. Goa saw the highest rate of additions, at 3.01%.

Bihar, which was the first State to undergo the SIR process in 2025 saw 13.89 lakh names being added to the final post-SIR list. Rajasthan saw more than 11.48 lakh voters being added to the final SIR voter list, followed by Uttarakhand (1.19 lakh), Madhya Pradesh (8.9 lakh), and Tamil Nadu (10.39 lakh).

The SSR, on hold since the SIR process began last year, was first announced in 17 States and Union Territories, including poll-bound Uttarakhand, Uttar Pradesh, and Punjab, on October 15. On November 5, it was expanded to six more States where the SIR process is over, and on November 16, it was announced that the SSR would also be conducted in Karnataka and Meghalaya.

Changing rolls

The combined electorate in the **13** States and U.T.s where draft SSR rolls have been published as of Tuesday saw a cumulative increase of **1.64%**

Voters in the 13 States/U.T.s

- Before SIR: **49.61** crore
- After SIR: **45.22** crore
- Draft SSR: **45.96** crore

Of these, the draft SSR rolls have been published for 15 States and Union Territories. The data for Punjab and Gujarat, however, was not available.

The SSR, an annual exercise, usually seeks to enrol eligible voters, particularly young and first-time electors, and facilitate advance applications from those who will become eligible on April 1, July 1, and October 1, 2027. However, it had not been carried out after the SIR was launched last year, an anomaly that was recently highlighted by Election Commissioners S.S. Sandhu and Vivek Joshi.

SIR HEARING
» PAGE 5

महत्वपूर्ण तथ्य

- BNSS Section 163
- Article 19 (1)
- Article 19 (3)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- ECI
- CEC – EC's
- SIR
- RPA 1950 – 21(3)
- RPA 1950 – 28 (RER-1960 - 6,7,8)
- RPA 1951 - 29(A)
- Conduct of Election Rules 1961 – 4(A) – Form 26

महत्वपूर्ण तथ्य

Shiv Sena row: dissent is not defection, says Shinde faction to SC

Press Trust of India
NEW DELHI



Arguments in the SC remained inconclusive and will resume on Wednesday. FILE PHOTO

The Eknath Shinde faction on Tuesday defended its legislators in the Supreme Court, saying that dissent is not defection and a legislator may dissent from the then leadership and oppose the course adopted without ceasing to be a member of the Shiv Sena.

Senior advocate Mahesh Jethmalani, appearing for Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde and other MLAs, told a Bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana that the legislators who dissented against the Uddhav Thackeray-led party leadership in June 2022 did not abandon the Shiv Sena but were seeking to restore the party's original ideological identity and political alignment.

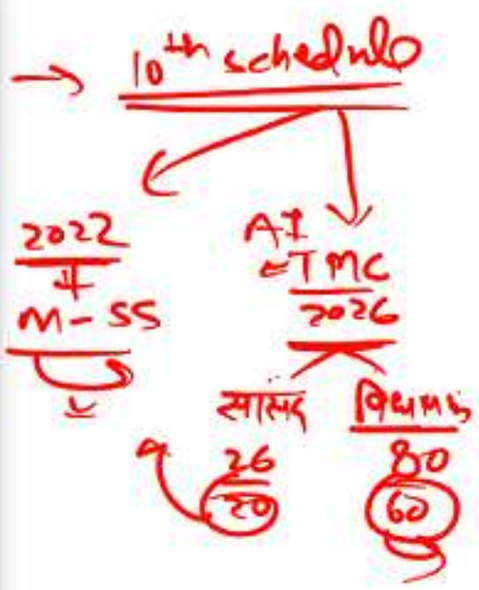
Mr. Mehta referred to the Tenth Schedule of the Constitution, also known as the anti-defection law, which contains provisions relating to disqualification on the ground of defection.

"Dissent is not defection," he said, adding that the disqualification clause can be invoked on issues relating to voting on confidence or no-confidence motion and matters relating to programmes of the political parties. He said the anti-defection provisions are intended to curb political defections and horse-trading, not suppress dissent or differences within a political party.

Decision challenged

The lead plea, filed by Sunil Prabhu of the Uddhav Thackeray faction, challenges the Assembly Speaker's 2024 decision declining to disqualify the MLAs of the Shinde faction under the Tenth Schedule.

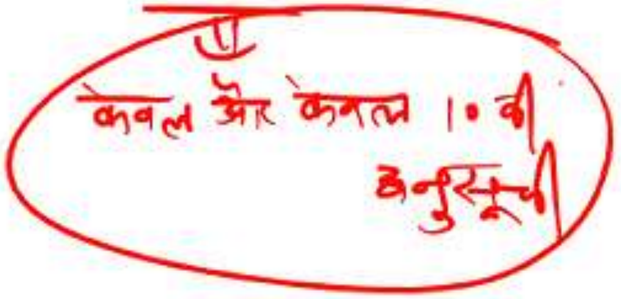
A connected plea filed by Mr. Thackeray challenges the EC's decision recognising the Shinde faction as the official Shiv Sena and allotting it the party symbol. The arguments remained inconclusive and will resume on Wednesday.





YouTube Homework

- **Political Parties**



महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय संविधान की **दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)** को सामान्यतः **'दलबदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law)** के रूप में जाना जाता है।
- इसे **52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से राजीव गांधी सरकार के दौरान संविधान में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल (Aya Ram, Gaya Ram की संस्कृति) को रोकना और सरकारों में स्थिरता बनाए रखना था।
- दसवीं अनुसूची से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. अयोग्यता के आधार (Grounds for Disqualification):

- दसवीं अनुसूची के तहत संसद (लोकसभा और राज्यसभा) तथा राज्य विधानमंडलों (विधानसभा और विधान परिषद) के सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है:
- **स्वैच्छिक सदस्यता त्यागना:** यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
- **व्हिप (Whip) का उल्लंघन:** यदि कोई सदस्य सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों (व्हिप) के विरुद्ध जाकर वोट करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है (और पार्टी द्वारा 15 दिन के भीतर उसके इस कृत्य को माफ नहीं किया गया हो)।
- **निर्दलीय सदस्य:** यदि कोई निर्दलीय (Independent) चुना गया सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- **मनोनीत सदस्य:** यदि कोई मनोनीत (Nominated) सदस्य सदन की शपथ लेने के **6 महीने के बाद** किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

2. दलबदल कानून के अपवाद (Exceptions):

- कुछ खास परिस्थितियों में पार्टी बदलने पर सदस्यता रद्द नहीं होती:
- **दलों का विलय (Merger):** यदि किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय हो जाता है और उस दल के **कम से कम दो-तिहाई (2/3)** सदस्य इस विलय के पक्ष में हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। (नोट: मूल कानून में 'विभाजन' के लिए 1/3 सदस्यों की छूट थी, जिसे 2003 के 91वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया)।
- **पीठासीन अधिकारी:** यदि कोई सांसद या विधायक लोकसभा अध्यक्ष (Speaker), सभापति या उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, तथा पद छोड़ने के बाद वापस पार्टी में लौट आता है, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. निर्णय लेने का अधिकार (Deciding Authority):

- दलबदल से जुड़े अयोग्यता के मामलों पर अंतिम निर्णय संबंधित सदन के **पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति)** द्वारा लिया जाता है।

4. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review):

- **मूल प्रावधान:** मूल कानून के अनुसार पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम था और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
- **सुप्रीम कोर्ट का फैसला (1992):** *किहोटो होलोहन मामले (Kihoto Hollohon Case)* में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है (यानी इसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है)। हालांकि, अदालतें आमतौर पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लेने से पहले हस्तक्षेप नहीं करती हैं।

5. प्रमुख संशोधन:

- **91वां संविधान संशोधन (2003):** इस संशोधन के तहत दलबदल के प्रावधानों को और सख्त किया गया। इसके तहत 'पार्टी में विभाजन' (Split) के आधार पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया, और मंत्रियों की संख्या की सीमा (कुल सदस्यों का अधिकतम 15%) तय की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

Gen Z is the torchbearer for global change: Prince William

At the 2026 Earthshot Prize ceremony, Britain's prince reflects on achievements of the finalists and the global movement behind environmental innovation; Bhutan, Mahindra Last Mile Mobility were among the five winners of this year's awards

Vinaya Deshpande Pandit
Yohaan Varghese
MUMBAI



Prince Williams and Princess Catherine with the winners of the 2026 Earthshot Prize in Mumbai on Tuesday. EMMANUAL YOGINI

Young people from around the world are not waiting for someone else to find the solution, they are the torchbearers of the global movement for change, Britain's Prince William said here on Tuesday.

He was speaking at the 2026 Earthshot Prize awards ceremony, which was held in India for the first time.

Winners of the Earthshot Prize were declared under five categories in a glittering ceremony. The awardees include the Himalayan Kingdom of Bhutan and Mahindra Last Mile Mobility.

'Shaping the future'

"They (Gen Z) are bringing fresh ideas and showing what is possible when optimism is matched with action. Their ideas, their energy, and their determination are helping to shape the future," he said.

"India is a nation of extraordinary innovation, ambition, facing immense environmental pressures, yet moving ahead with determination. Not because the challenge is simple, not because the path is easy. But because millions of people have decided that progress simply cannot wait," he said.

During his address, Prince William reflected on the achievements of this year's finalists and the growing global movement behind environmental innovation.

The ceremony was attended by environmental innovators, philanthropists, business leaders, government representatives and global figures from sport, entertainment and culture.

Mahindra Last Mile Mobility won the Earthshot Prize in the 'Clean Our Air' category. Accepting the award, the company's CEO, Suman Mishra, said it showed how urgent optimism worked. The company has won £1 million for its efforts, which have resulted in more electric three-wheelers plying on India's roads.

In the 'Revive Our Oceans' category, Niue Ocean Wide Trust was chosen for protecting the oceans, especially the vast Pacific region.

Coral Pasisi, vice chair and co-architect of Ocean Conservation Commitments, expressed gratitude for indigenous, people-led sustainability efforts being honoured.

"It is collective responsibility in action. We want to protect the oceans that protect us all," she said while accepting the award.

The Earthshot Prize to Protect and Restore Nature was awarded to Bhutan for the country's work in protecting the Himalayan forests, which help the water systems that sustain 1.6 billion people downstream across South Asia.

While accepting the award, Bhutan's Princess Chimi Yangzom Wangchuck said: "Long before environmentalism become a global priority, Bhutan made a national commitment. 60% of our land must remain under forest cover at all times. A duty enshrined in our Constitution. Deeply honoured to accept this prize."

The Earthshot Prize in the 'Build a Waste-free World' category was declared for PFAS - Free France. The initiative is a national, cross-party movement to ban toxic forever chemicals in consumer products and to make polluters pay for the clean-up.

"This victory belongs to all those who stood by us and said, 'We will not be poisoned in silence'. Thank you," said Nicolas Thierry, French politician and lead spokesperson of the firm, while accepting the award.

Orsed was declared the winner in the 'Fix Our Climate' category for transforming its business from coal-intensive utilities to renewable energy.

The ceremony was hosted by director Karan Johar. Among the celebrities who took to stage were British actress and musician Simone Ashley, actor and previous Earthshot Awards presenter Rami Malek, Indian cinema stars Alia Bhatt and Sonam Kapoor, and cricket legend Sachin Tendulkar.

Earthshot Prize → Mumbai

YouTube Homework

- Nobel Prize

महत्वपूर्ण तथ्य

- **अर्थशॉट पुरस्कार (The Earthshot Prize)** जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकटों के व्यावहारिक व नवीन समाधान (Innovative Solutions) खोजने और उन्हें वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार है। इसे **प्रिंस विलियम** और **सर डेविड एटनबरो** द्वारा **2020** में शुरू किया गया था।
- 2026 के संस्करण से जुड़ी प्रमुख जानकारी नीचे दी गई है:

1. भारत में आयोजन (स्थान और तिथियाँ)

- **स्थान:** अर्थशॉट पुरस्कार 2026 (छठा संस्करण) भारत की आर्थिक राजधानी **मुंबई (महाराष्ट्र)** में आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब इस पुरस्कार समारोह की मेज़बानी भारत ने की।
- **कब से कब तक:** अर्थशॉट वीक और संबंधित कार्यक्रम **नवंबर 2026 के पहले सप्ताह** (मुख्य रूप से **4 से 7 नवंबर 2026** के आसपास) मुंबई में आयोजित हुए, जिसमें मुख्य पुरस्कार समारोह **6 नवंबर 2026** को संपन्न हुआ।

2. पुरस्कार राशि और श्रेणियाँ

- हर साल पर्यावरण से जुड़ी **पाँच मुख्य श्रेणियों** में एक-एक विजेता चुना जाता है, और प्रत्येक विजेता को अपने प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए **1 मिलियन पाउंड (£1 Million — लगभग ₹11 करोड़)** की पुरस्कार राशि दी जाती है।

3. अर्थशॉट पुरस्कार 2026 के विजेता (5 श्रेणियाँ)

- 2026 में दुनिया भर से चुने गए 15 फाइनलिस्ट में से निम्नलिखित 5 संगठनों को विजेता घोषित किया गया:
- **प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना (Protect and Restore Nature):**
  - **विजेता: नेचरमेट्रिक्स (NatureMetrics — यूनाइटेड किंगडम)** — पर्यावरणीय डीएनए (eDNA) तकनीक के माध्यम से जैव विविधता की निगरानी करने और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए।
- **हवा को स्वच्छ बनाना (Clean Our Air):**
  - **विजेता: महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी (Mahindra Last Mile Mobility — भारत)** — भारत में किफायती इलेक्ट्रिक तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के माध्यम से शहरी वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए।
- **महासागरों को पुनर्जीवित करना (Revive Our Oceans):**
  - **विजेता: कोस्टल विलेजेंस / हाई सीज़ अलायंस पहल (Coastal & Marine Conservation)** — तटीय समुदायों के नेतृत्व में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) के संरक्षण के लिए।
- **कचरा-मुक्त दुनिया का निर्माण (Build a Waste-Free World):**
  - **विजेता: सर्कुलर पैकेजिंग / वेस्ट-टू-वैल्यू पहल** — औद्योगिक और प्लास्टिक कचरे को कम करने और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल विकसित करने के लिए।
- **जलवायु को ठीक करना (Fix Our Climate):**
  - **विजेता: क्लीन एनर्जी / ग्रीन इंडस्ट्रियल हीट सॉल्यूशन** — भारी उद्योगों में जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक प्रदान करने के लिए।

महत्वपूर्ण तथ्य



Rajnath Singh to visit Japan today for Ministerial dialogue

Defence Minister Rajnath Singh will visit Japan on November 18 and 19 to participate in the fourth edition of the India-Japan Foreign and Defence Ministers' Dialogue (2+2) and hold bilateral discussions with his Japanese counterpart, with a focus on strengthening defence cooperation, maritime security and defence industrial partnerships. The 2+2 Ministerial Dialogue, scheduled to be held in Tokyo, will be co-chaired by Mr. Singh and External Affairs Minister S. Jaishankar, along with Japan's Defence Minister Shinjiro Koizumi and Foreign Minister Toshimitsu Motegi. The meeting between Mr. Singh and Mr. Koizumi will be their third this year.

⇒ 2+2 मन्त्रिस्तरीय वार्ता
Japan – India
रक्षा | विदेश | रक्षा | विदेश
Fourth
18-19 Nov. 2026
Tokyo
=
विश्वकप
SCO (Council of Heads of Govt.)
SCO
PM
SCO Heads of Govt.
SCO civilized Dialogue Forum – New Delhi

YouTube Homework

- 13th ADMM – Cebu
- 25th SCO Council of Heads of Government (CHG) – दुशाम्बे

▷ अन्य कौनसे देशों के साथ 2+2 वार्ता हो रही है

महत्वपूर्ण तथ्य

- चौथी **भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (4th India-Japan 2+2 Ministerial Dialogue)** से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ और इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

आयोजन से जुड़ी मुख्य बातें (Kab, Kaha aur Kaise):

- **कब हुई / कब से कब तक:** यह वार्ता **18 और 19 नवंबर 2026** को आयोजित की गई है।
- **कहाँ हुई:** यह बैठक जापान की राजधानी **टोक्यो (Tokyo)** में संपन्न हुई है।
- **किसने की सह-अध्यक्षता:**
  - **भारत की ओर से:** रक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** और विदेश मंत्री **डॉ. एस. जयशंकर** ने इस उच्चस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।
  - **जापान की ओर से:** जापान के रक्षा मंत्री **शिंजिरो कोइजुमी (Shinjiro Koizumi)** और विदेश मंत्री **तोशिमित्सु मोतेगी (Toshimitsu Motegi)** शामिल रहे।

इस वार्ता के प्रमुख बिंदु (Major Points):

- **मुक्त और खुला इंडो-पैसिफिक (Free & Open Indo-Pacific):**
  - दोनों देशों ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित (Rules-based) हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को पुरजोर तरीके से दोहराया।
- **रक्षा उपकरणों और तकनीक का सह-विकास (Defence Technology & Co-development):**
  - दोनों पक्षों ने रक्षा उपकरणों और उन्नत सैन्य तकनीकों के संयुक्त विकास तथा औद्योगिक साझेदारी (Industrial Synergy) को गहरा करने की दिशा में रोडमैप पर चर्चा की।
- **समुद्री सुरक्षा (Maritime Security):**
  - क्षेत्रीय जलक्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर सहमति बनी।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास (Joint Military Exercises):**
  - भारत और जापान की तीनों सेनाओं (थलमार्ग, जलमार्ग और वायुमार्ग) के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों के दायरे, पैमाने और उनकी जटिलता को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- **रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा:**
  - मंत्रियों ने भारत-जापान के बीच 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' (Special Strategic and Global Partnership) के पूरे दायरे की समीक्षा की तथा आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कूटनीतिक संबंधों को नई ऊँचाइयाँ देने पर चर्चा की।

महत्वपूर्ण तथ्य

Horticultural production shows 4.36% growth: govt.

The Hindu Bureau
NEW DELHI



The rise in production came despite a reduction in the area under horticultural cultivation, says Union Agriculture Minister. FILE PHOTO

India's total horticultural production is expected to reach 3,869.15 lakh tonnes in 2025-26, an increase of 161.77 lakh tonnes (4.36%) over the production recorded in 2024-25, according to the third advanced estimates of area and production of horticultural crops released by Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan in New Delhi on Tuesday. In the previous crop season, horticulture production stood at 3,707.38 lakh tonnes.

Mr. Chouhan expressed satisfaction over the projected growth and said the significant increase in horticultural production reflected the hard work of India's farmers and the impact of the Union government's farmer-friendly policies. "This record production would not only strengthen the country's nutritional security but also directly contribute to higher incomes for horticulture farmers," the Minister said, congratulating farmers across the country for their efforts.

Farmers were increasingly moving beyond traditional crops towards the cultivation of fruits, vegetables, flowers, spices, and plantation crops, including cashew, coconut and cocoa, as well as aromatic and medicinal plants, he said.

"This growing interest in commercial and high-value crops is opening up new avenues of income for farmers while creating fresh opportunities for self-reliance and growth in the agricultural sector," Mr. Chouhan said.

He added that one of the most significant aspects of the latest estimates was an increase in production despite a reduction in the area under horticultural cultivation.

⇒ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
↳ 2024-25
↳ Third Advance estimates of Area and Production of horticultural crops

महत्वपूर्ण तथ्य

- बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का **तीसरा अग्रिम अनुमान (Third Advance Estimate of Area and Production of Horticulture Crops)** भारत सरकार के **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare)** द्वारा जारी किया जाता है।

1. यह रिपोर्ट क्या है? (What is it?)

- यह एक वार्षिक सांख्यिकीय अनुमान है, जो देश भर में **फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, सुगंधित एवं औषधीय पौधों और रोपण फसलों (Plantation Crops)** के कुल बुवाई क्षेत्र (Area) और संभावित उत्पादन (Production) का विवरण प्रस्तुत करता है।
- यह अनुमान राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है।

2. इसे कौन जारी करता है? (Issuing Authority)

- इसे केंद्रीय **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture & Farmers' Welfare - DA&FW)** द्वारा जारी किया जाता है।

3. इसके प्रमुख घटक (Major Components Covered):

- इस अनुमान में मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों का आकलन किया जाता है:
- **फल (Fruits):** आम, केला, अंगूर, सेब, अमरूद, संतरा, पपीता आदि।
- **सब्जियां (Vegetables):** आलू, प्याज, टमाटर (TOP फसलों सहित), बैंगन, गोभी, भिंडी आदि।
- **बागानी / रोपण फसलें (Plantation Crops):** नारियल, सुपारी, काजू, कोको आदि।
- **मसाले (Spices):** हल्दी, मिर्च, अदरक, जीरा, लहसुन, धनिया आदि।
- **अन्य:** फूल (Aromatic & Medicinal Plants) और शहद (Honey) उत्पादन के आंकड़े भी प्रायः इसी के साथ शामिल किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

4. महत्वपूर्ण

- **खाद्यान्न बनाम बागवानी उत्पादन:** पिछले कई वर्षों से भारत में कुल बागवानी उत्पादन (Total Horticulture Production), कुल खाद्यान्न उत्पादन (Total Foodgrain Production) से **अधिक** रहा है। यह भारतीय कृषि के विविधीकरण (Diversification) और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- **सब्जियों और फलों का हिस्सा:** कुल बागवानी उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा **सब्जियों (Vegetables)** का होता है (लगभग 55-60%), जिसके बाद **फलों (Fruits)** का स्थान आता है (लगभग 30-32%)।
- **खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन (Food Inflation Management):** प्याज, टमाटर और आलू (TOP) जैसी संवेदनशील फसलों के उत्पादन के अग्रिम अनुमान सरकार को निर्यात-आयात नीति तय करने, बफर स्टॉक बनाने और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- **आत्मनिर्भरता और निर्यात:** बागवानी क्षेत्र किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि निर्यात बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

President hails country's progress in malaria control

The Hindu Bureau
NEW DELHI

President Droupadi Murmu inaugurated the golden jubilee celebrations of the Indian Council of Medical Research-National Institute of Malaria Research (ICMR-NIMR) here on Tuesday.

The President highlighted India's progress in malaria control, noting that malaria cases and deaths had declined by nearly 80% between 2015 and 2025, while the number of high-burden districts fell from 155 to 33. She also noted that 160 districts reported zero indigenous malaria cases during 2022-2025.

Appreciating India's exit from the World Health Organization (WHO)'s High Burden to High Impact (HBHI) group in 2024, she acknowledged the collective efforts of scientists, healthcare workers, and citizens. She also recognised ICMR-NIMR's contribution over five decades to research on malaria parasites, mosquito vectors, vector control, insecticide resistance, and community surveillance.



President Droupadi Murmu visiting an exhibition stall at the ICMR-National Institute of Malaria Research on Tuesday. X/ANI

Continued vigilance

Emphasising the need for continued vigilance and effective interventions, Ms. Murmu called for strengthened malaria diagnosis, treatment and surveillance, mosquito control, development of new medicines and vaccines, greater public awareness, and community participation.

She stressed that scientific research and its outcomes should reach villages and communities where they are most needed. She also expressed satisfaction over ICMR-NIMR's contribution to the indigenous malaria vaccine being developed in Bhubaneswar and voiced confidence that it would support India's malaria elimination efforts.

महत्वपूर्ण तथ्य

राष्ट्रपति ने मलेरिया नियंत्रण में देश की प्रगति की सराहना की

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को यहाँ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (ICMR-NIMR) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया।

मुख्य अंश और सारांश (Summary of the Article):

- **प्रगति के आंकड़े:** राष्ट्रपति ने मलेरिया नियंत्रण में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 2015 से 2025 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में लगभग 80% की गिरावट आई है, जबकि उच्च-भार (high-burden) वाले जिलों की संख्या 155 से घटकर 33 रह गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2022-2025 के दौरान 160 जिलों में स्थानीय मलेरिया का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।
- **डब्ल्यूएचओ (WHO) की सूची से बाहर होना:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 'हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट' (HBHI) समूह से 2024 में भारत के बाहर निकलने की सराहना करते हुए, उन्होंने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को स्वीकार किया। उन्होंने मलेरिया परजीवियों पर शोध, मच्छर वाहकों (vectors), वेक्टर नियंत्रण, कीटनाशक प्रतिरोध और सामुदायिक निगरानी पर पांच दशकों से अधिक के शोध में ICMR-NIMR के योगदान की भी सराहना की।
- **सतत सतर्कता (Continued vigilance):** निरंतर सतर्कता और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने मलेरिया की जाँच, उपचार और निगरानी, मच्छर नियंत्रण, नई दवाओं और टीकों के विकास, जन जागरूकता तथा सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने का आह्वान किया।
- **जमीनी स्तर पर शोध:** उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक अनुसंधान और उसके परिणाम उन गांवों और समुदायों तक पहुंचने चाहिए जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
- **स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन:** उन्होंने भुवनेश्वर में विकसित की जा रही स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन में ICMR-NIMR के योगदान पर संतोष व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यह भारत के मलेरिया उन्मूलन प्रयासों में मददगार साबित होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत से मलेरिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, हालांकि देश इसे जड़ से खत्म करने के लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार ने 2027 तक देश में मलेरिया के स्थानीय मामलों को शून्य करने और 2030 तक पूर्ण मलेरिया उन्मूलन (elimination) का लक्ष्य रखा है।
- भारत में मलेरिया की वर्तमान स्थिति और प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

मलेरिया नियंत्रण में भारत की बड़ी उपलब्धियां

- मामलों और मौतों में भारी गिरावट. 2015 से 2025 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में लगभग 80% की कमी दर्ज की गई है।
- अधिक प्रभावित जिलों में कमी. देश में मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित (High-burden) जिलों की संख्या 155 से घटकर अब केवल 33 रह गई है।
- मलेरिया-मुक्त जिले. 2022 से 2025 के बीच भारत के 160 जिलों में मलेरिया का एक भी स्थानीय मामला दर्ज नहीं किया गया है।
- वैश्विक स्तर पर सुधार. दुनिया की लगभग 16% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक मलेरिया मामलों में भारत की हिस्सेदारी घटकर लगभग 0.7% और मौतों में 0.6% रह गई है।
- WHO सूची से बाहर. शानदार प्रगति के कारण भारत 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 'High Burden to High Impact' (अधिक बोझ वाले देशों के) समूह से आधिकारिक तौर पर बाहर निकल गया है।

आगे की चुनौतियां

- प्रभावित क्षेत्र. कुछ आदिवासी, दुर्गम और वन क्षेत्रों (जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों) में अब भी मलेरिया के मामले सामने आते हैं।
- नए खतरे. जलवायु परिवर्तन, मच्छरों के व्यवहार में बदलाव और दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता (drug resistance) जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार निगरानी और स्वदेशी वैक्सीन पर काम जारी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Voyager 1, one light-day away from earth today, is a marvel of science

Measurements lying in the shadows of their successors can find new lives in the light of new theories. The Voyager 1 mission's longevity made that more apparent, allowing successive generations of researchers to find more uses for its data even as it continues to collect new information

Vasudevan Mukunth

Today, the Voyager 1 spacecraft will be one light-day away from the earth. This means a signal travelling at the speed of light will take one full day to go from the earth to Voyager 1, and signals from the spacecraft will similarly take one day to reach receivers on the earth.

This is a tremendous distance – almost 26 billion kilometres. Since February 17, 1998, Voyager 1 has been the farthest any space mission has been from us. And it keeps going at 61,000 km/hr. But even at such breathtaking speed, Voyager 1 is still barely out of the solar system. Each star's gravitational and magnetic fields extend out for billions of kilometres around them, bending the destinies of multiple worlds to their stellar will.

It is no surprise then that Voyager 1 has itself been defined by superlatives for providing a sense of the influence of our own sun: the first, the farthest, and indeed the oldest space mission still going.



An artist's rendering of Voyager 1 barrelling through space. NASA

Pleasant surprise

When NASA launched Voyager 1, the Soviet Union was still a country, the Berlin Wall divided Germany, apartheid was law in South Africa, and neither the World Wide Web nor smartphones existed. Voyager 1 itself has changed during its mission: its operators switched off its cameras in 1980, replaced its ageing components with backups, and, by 2020, left only two of its six science instruments online – but the superlatives have often obscured the important scientific contributions these instruments have themselves made.

For example, scientists were in for a pleasant surprise when they found that one of the instruments onboard Voyager 1 was actually tracking galactic cosmic rays even though it was not designed to. The ultraviolet spectrometer's purpose was to study ultraviolet light, released by gases of dust scattering sunlight in space and by the atmospheres of distant planets. The detector also registered noise from other sources, including from Voyager's nuclear power source, and scientists routinely subtracted it from the data to reveal the ultraviolet signals.

But in 2008, researchers reported in the journal *Astronomy & Astrophysics* that the background noise was actually created by cosmic rays – high-energy particles coming from beyond the solar system. They reanalysed this data collected between 1992 and 2005 and compared them to other instruments elsewhere that were tracking cosmic rays, and concluded the ultraviolet spectrometer onboard Voyager 1 was indeed sensitive to cosmic rays within a small energy range.

Little surprises

The team also sought independent evidence in this data to check whether Voyager 1 had reached or crossed the heliopause, the boundary of the region dominated by the solar wind, in 2012, although the implications went further.

For example, the spectrometer's unexpected readings raised questions about the part of space immediately inside the heliopause, where the solar wind seemed to flow more slowly. After more study, scientists proposed that the wind braked due to interactions between the subatomic particles it contained and the electrically neutral atoms from interstellar space. The proposal remains unconfirmed but nonetheless offered a new way to investigate the possibility that the heliopause may look different in different directions.

Voyager 1 has sprung many little surprises of similar nature that have often slipped the public eye. For another example, when Voyager 1 came close to Saturn, its instruments collected data scientists subsequently used to test one of Albert Einstein's predictions: that the frequency of electromagnetic radiation, such as light, changes when it passes through a gravitational field.

In a study published in *Physical Review Letters* in March 1990, researchers confirmed the prediction with 0% accuracy – a rare instance of an interplanetary mission contributing to fundamental physics. To be fair, the Voyager 1 result also depended on an assumption that radiation around Saturn did not interfere with the spacecraft's frequency reference.

Second, the NASA Gravity Probe A experiment had already confirmed Einstein's prediction in 1976, that too within a better accuracy of 0.02%. The finding based on Voyager 1 was nonetheless interesting because it was independent: based on wholly different instruments and from within a distinct planetary environment. Physicists seek such differences because there are alternative theories of gravity that, on paper, predict varying effects in varying conditions, and differences in the observed data could challenge theories that do not predict them.

Stepping stones

In the same visit to Saturn, scientists also used the radio signals Voyager 1 could emit to study the planet's rings. Specifically, as the spacecraft moved behind the rings, its signals bound for the earth travelled through the rings first, and by studying how the signals were scattered and weakened, scientists could piece together the distribution of materials in the rings.

Thus they discovered fine structures such as narrow gaps between the rings and wave-like undulations in their density, and determined that the particles making up the rings were at best 10-20 metres wide in certain regions.

Operators repeated the same technique with Saturn's moon Titan, which is the only moon in the solar system with a substantial atmosphere, and the only other planetary body to have liquids on its surface. When the Voyager 1 radio transmissions travelled through Titan's atmosphere, scientists were able to measure its temperature and pressure.

Both sets of findings were stepping stones for the landmark NASA Cassini mission, which studied the Saturnian system up-close from 2004 to 2017. The data also informed plans for the mission's Huygens probe, which descended through Titan's atmosphere in 2005.

Measurements lying in the shadows of their successors can find new lives in the light of new theories. The Voyager 1 mission's longevity made that more apparent, allowing successive generations of researchers to find more uses for its data even as it continues to collect new information.

As it pulls further away from the earth, its signals will grow dimmer and its instruments will eventually fall silent, but the scientific life of its observations will keep going.

vasudevan.mukunth@thehindu.co.in

THE GIST

Voyager 1's most unexpected discovery came when its ultraviolet spectrometer, designed to study UV light, was found to be unintentionally detecting galactic cosmic rays. Scientists later realised the instrument was providing useful data on cosmic rays.

When the spacecraft came close to Saturn, its instruments collected data scientists subsequently used to test one of Albert Einstein's predictions. His result was notable for providing independent confirmation, albeit to a weaker degree than ideal, of a concept in fundamental physics.

Voyager 1's radio signals revealed detailed structures in Saturn's rings and helped measure the temperature and pressure of Titan's atmosphere; these findings laid the groundwork for the later Cassini-Huygens mission.

YouTube Homework

- Artemis Mission

महत्वपूर्ण तथ्य

- वॉयेजर 1 (Voyager 1) हाल-फ़िलहाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि 18 नवंबर 2026 को यह पृथ्वी से 'वन लाइट-डे' (एक प्रकाश-दिन) यानी लगभग 25.9 अरब किलोमीटर की ऐतिहासिक दूरी तय करने वाला पहला मानव-निर्मित यान बन रहा है। इस दूरी पर पृथ्वी से भेजे जाने वाले रेडियो संकेतों को यान तक पहुंचने में पूरे 24 घंटे का समय लगेगा।

वॉयेजर 1 क्या है?

- अंतरिक्ष यान (Space Probe). यह लगभग 815 किलोग्राम वज़नी एक मानव-रहित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है।
- सबसे दूर स्थित मानव-निर्मित वस्तु. यह पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित मानव-निर्मित वस्तु है। यह वर्तमान में लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है।
- गोल्डन रिकॉर्ड (Golden Record). इस यान में तांबे पर सोने की परत चढ़ा हुआ एक ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड रखा गया है। इसमें पृथ्वी की तस्वीरें, प्राकृतिक ध्वनियाँ, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन दर्ज हैं ताकि भविष्य में किसी बाहरी सभ्यता को मानवता का परिचय मिल सके।

प्रक्षेपण (Launch) किसके द्वारा किया गया?

- संस्था. इसका निर्माण और प्रक्षेपण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) द्वारा किया गया।
- रॉकेट और स्थान. इसे केप कैनावेरल (फ्लोरिडा) से टाइटन IIIE-सेंटौर (Titan IIIE-Centaur) रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया।

इसका उद्देश्य क्या है?

- प्राथमिक उद्देश्य. इसका शुरुआती लक्ष्य हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों बृहस्पति (Jupiter), शनि (Saturn) और शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन (Titan) का नज़दीक से अध्ययन करना था। इसने इन ग्रहों के छल्लों (Rings), वायुमंडल और नए चंद्रमाओं की खोज की।
- वर्तमान उद्देश्य. ग्रहों का अध्ययन पूरा करने के बाद इसका उद्देश्य सूर्य के प्रभाव क्षेत्र (Heliosphere) से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस (Interstellar Space) यानी तारों के बीच के खाली स्थान, चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांडीय किरणों का डेटा पृथ्वी पर भेजना है।

मिशन कब से कब तक है?

- शुरुआत. इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। मूल रूप से इसे केवल चार से पाँच वर्षों के मिशन के लिए बनाया गया था।
- प्रमुख पड़ाव. इसने 1979 में बृहस्पति और 1980 में शनि के पास से गुज़रते हुए डेटा एकत्र किया। 25 अगस्त 2012 को यह सौरमंडल की सीमा (Heliopause) पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला यान बना।
- अंत कब होगा. यह मिशन पिछले 49 वर्षों से लगातार सक्रिय है। इसमें लगा प्लूटोनियम ईंधन हर साल कम हो रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को ऊर्जा बचाने के लिए इसके उपकरण धीरे-धीरे बंद करने पड़ रहे हैं। नासा (NASA) के अनुमान के अनुसार, यह यान लगभग 2030 से 2036 के बीच पृथ्वी से संपर्क करने की अपनी ऊर्जा पूरी तरह खो देगा, हालांकि इसकी अंतरिक्ष यात्रा अनंत काल तक जारी रहेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

WHAT IS IT?

LineShine stays defending champ

Vasudevan Mukunth

China's LineShine supercomputer has retained its top spot in the list of the world's most powerful supercomputers, the latest edition of which was released at the SC26 conference in Chicago on Monday. LineShine first summited this list in June this year, where it displaced the U.S. El Capitan.

The updated list is also remarkable because its top 10 machines are unchanged from June. The overall 500 admitted only 27 newcomers in this time — the lowest in history — although the reason is obvious: the amount of computing power required to enter the list increased by 7.3% in the same period. The highest-ranked newcomer was HANGANG in South Korea, at number 12.

The Shenzhen Cloud Computing Centre built and installed LineShine at the National Supercomputing Centre in the same city. It is the first Chinese supercomputer to lead the Top500 since Sunway TaihuLight did in 2017.

During one standardised test, engineers found LineShine could perform up to 2.198 quintillion calculations per second, becoming the first Top500 machine to cross the 2 quintillion mark. During the same test it consumed around 42 MW of power. Researchers built LineShine for atmospheric and ocean research.

It uses China-made processors and an operating system called Kylin. Its topping the Top500 is thus a vote of confidence for China against the backdrop of the U.S. restricting its access to advanced computing chips.



World's fastest: China's LineShine supercomputer has retained the top spot in the latest Top500 rankings XINHUA

After LineShine and El Capitan, the top five include Frontier and Aurora, also in the U.S., and JUPITER Booster in Germany. The highest ranked Indian machine on the list is Shakti Cloud at #35.

For feedback and suggestions
for 'Science', please write to **science@thehindu.co.in** with the subject 'Daily page'

महत्वपूर्ण तथ्य

- LineShine (लाइनशाइन) चीन का एक बेहद शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर है, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर है। 2026 की TOP500 रैंकिंग (जून और नवंबर दोनों संस्करणों) में इसने अमेरिका के 'El Capitan' को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है।

1. LineShine सुपरकंप्यूटर की खास बातें

- स्थान और निर्माण. यह चीन के शेन्ज़ेन (Shenzhen) शहर में स्थित नेशनल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर में लगाया गया है। इसे पूरी तरह से चीनी तकनीक और घरेलू घटकों (components) का उपयोग करके बनाया गया है।
- रफ़्तार (Speed). इसकी गणना करने की गति 2.198 एक्साफ्लॉप्स (Exaflops) है। इसका मतलब है कि यह एक सेकंड में 2 क्विंटिलियन (2 के बाद 18 शून्य) से भी ज़्यादा गणनाएं कर सकता है।
- खास तकनीक (All-CPU आर्किटेक्चर). आजकल के ज़्यादातर आधुनिक सुपरकंप्यूटर तेज़ रफ़्तार के लिए महंगे GPUs (जैसे Nvidia के चिप्स) पर निर्भर रहते हैं। लेकिन LineShine दुनिया का पहला ऐसा 2-एक्साफ्लॉप सुपरकंप्यूटर है जो बिना किसी बाहरी GPU के, केवल चीन के अपने LX2 CPUs (कुल लगभग 1.37 करोड़ कोर) की मदद से चलता है।
- ऑपरेटिंग सिस्टम. यह चीन के खुद के बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम Kylin OS पर काम करता है।
- उपयोग. इसका इस्तेमाल मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने, नई दवाओं की खोज, जलवायु परिवर्तन के मॉडल तैयार करने और जटिल वैज्ञानिक शोधों में किया जाता है।

2. दुनिया के टॉप 5 सबसे ताकतवर सुपरकंप्यूटर और उनके देश

नवीनतम TOP500 लिस्ट के अनुसार दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर और संबंधित देश नीचे दिए गए हैं:

रैंक	सुपरकंप्यूटर का नाम	देश	रफ़्तार (HPL स्कोर)
1	LineShine	चीन (China)	2.198 Exaflops
2	El Capitan	अमेरिका (USA)	1.809 Exaflops
3	Frontier	अमेरिका (USA)	1.353 Exaflops
4	Aurora	अमेरिका (USA)	1.012 Exaflops
5	JUPITER Booster	जर्मनी (Germany)	1.000 Exaflops

(नोट: यदि आप केवल अलग-अलग टॉप 5 देशों के नाम जानना चाहते हैं जिनके पास सबसे ताकतवर सुपरकंप्यूटर हैं, तो टॉप 10 की सूची के आधार पर वे देश हैं: 1. चीन, 2. अमेरिका, 3. जर्मनी, 4. इटली (HPC6), और 5. जापान (Fugaku)।)

महत्वपूर्ण तथ्य

3. भारत (India) किस रैंक पर है?

- शीर्ष भारतीय सिस्टम. 2026 की TOP500 रैंकिंग में भारत का सबसे तेज़ कमर्शियल सिस्टम Shakti Cloud (Yotta Data Services द्वारा संचालित) 32वें स्थान पर है।
- सरकारी/स्वदेशी सुपरकंप्यूटर. भारत सरकार के 'नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन' (NSM) के तहत बने स्वदेशी सुपरकंप्यूटरों में AIRAWAT-PSAI (C-DAC, पुणे) लगभग 211वें से 219वें स्थान के आसपास रहा है। इसके अलावा भारत के स्वदेशी PARAM Rudra (GPU और CPU क्लस्टर) भी दुनिया के टॉप 500 सुपरकंप्यूटरों की सूची (रैंक 245 और 318) में शामिल हैं।
- कुल संख्या में स्थान. दुनिया के टॉप 500 सुपरकंप्यूटरों की कुल संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 18वें स्थान पर है (भारत के कुल 7 सिस्टम इस सूची में शामिल हैं)।

4. सबसे ज़्यादा सुपरकंप्यूटर किस देश के पास हैं?

- दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपरकंप्यूटर अमेरिका (USA) के पास हैं।
- 2026 की TOP500 सूची में शामिल 500 सबसे ताकतवर कंप्यूटरों में से 161 सुपरकंप्यूटर अकेले अमेरिका के पास हैं, जो दुनिया की कुल सुपरकंप्यूटिंग शक्ति का लगभग 37.5% हिस्सा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

IN-SPACe picks three firms to develop 3D reconstruction of Indian cities

The Hindu Bureau
BENGALURU

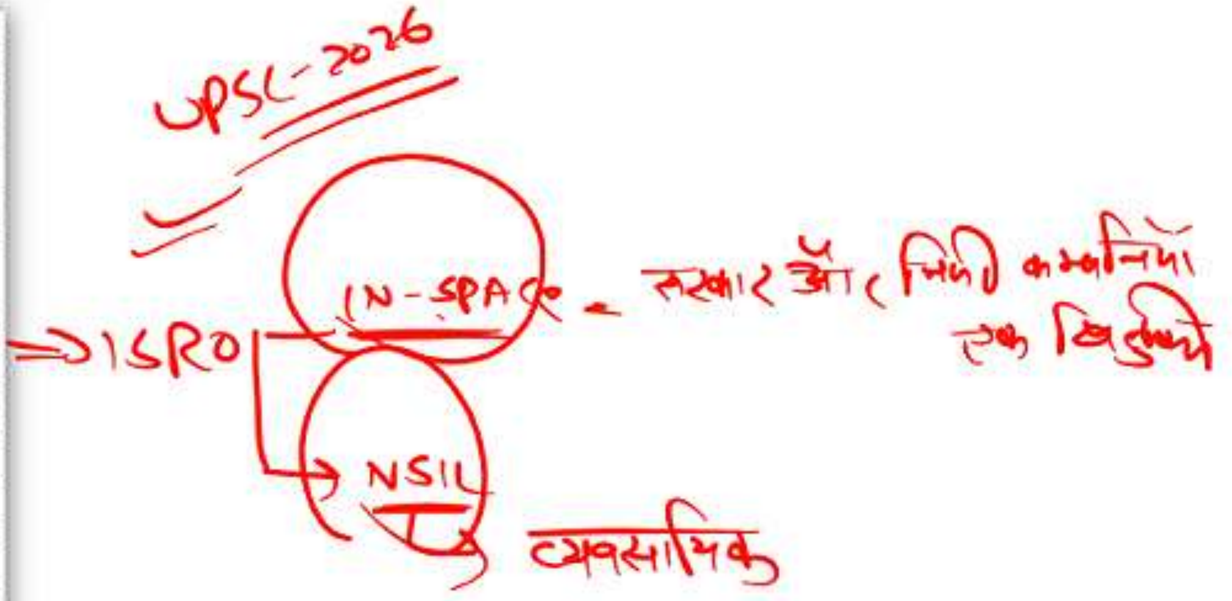
The Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe) has selected three Indian space companies to develop High-Resolution Indian Human Settlement Layers (IHSL) across Indian cities.

The three companies, SpacePixxel Technologies Pvt. Ltd., KaleidEO Space Systems Pvt. Ltd. and Azista Industries Pvt. Ltd. have been selected under IN-SPACe's Seed Fund Scheme for Use Case Demonstration by Non-Government Entities (NGEi) to develop IHSL across Indian cities.

These companies will collectively receive seed funding of ₹1.46 crore to develop and demonstrate an indigenous satellite-based system for 3D reconstruction of India's built environment using monocular imageries.

IN-SPACe said that the initiative aims to address the NITI Aayog's requirement of having an accurate and detailed geospatial data on human settlement which can be used for urban planning, infrastructure development and disaster risk assessment in addition to population assessment.

The selected companies will develop models using Earth Observation data to generate three integrated outputs covering built-up surface and building type, building height, and built-up volume.



महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

भारत का परमाणु कार्यक्रम

Bangladesh connects nuclear power plant to national grid on a trial basis

Press Trust of India
DHAKA

Bangladesh's first nuclear power plant at Rooppur in the country's northwest Pabna district began supplying electricity to the national grid on a trial basis on Tuesday, according to officials.

The 2,400 MW Russian-assisted facility is expected to meet more than 10% of Bangladesh's electricity demand once fully operational, helping the country diversify its energy sources.

"We have become the 33rd country in the world to produce and generate nuclear power," Science and Technology Minister Fakir Mahbub Anam told presspersons at the plant site.



An aerial view of the Rooppur Nuclear Power Plant near the Padma river at Ishwardi in Bangladesh's Pabna district. AFP

The development comes as the South Asian nation of 170 million people grapples with a fuel crisis triggered by the conflict in West Asia.

The plant comprises two units, each with a generation capacity of 1,200 MW, officials said, adding that the first unit has begun supplying 350 MW of electricity to the national grid. According to the Science and Technology Ministry, the initial connection would last between eight and 10 hours, during which engineers would conduct tests on the plant's turbine, generator and grid stability.

The first connection would last between eight and 10 hours, during which engineers would conduct tests

The unit would subsequently be disconnected for further technical tests and could be reconnected after about 28 hours for another four to six hours to complete additional operational checks.

Under an agreement with the Russian contractor, the first unit will undergo a 10-month trial operation before beginning commercial electricity generation at full capacity, the Ministry said.

Construction on the facility began in 2017 during the administration of ousted Prime Minister Sheikh Hasina, following a 2015 agreement with Moscow.

महत्वपूर्ण तथ्य

G-7 / BRICS / SCO + ASEAN + QUAD + APEC + East Asia Summit

World needs peace and predictability: Modi

- Quad leaders issue joint statement opposing economic, maritime 'coercion' in Indo-Pacific
- Modi proposes seafarers' safety initiative at East Asia Summit, attends meet with ASEAN leaders
- It is essential to ensure that our future is shaped not by competition, but cooperation, PM says

Suhasini Haidar
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi on Tuesday called for "peace, stability, and predictability" in the world as he attended three back-to-back summits, including the Quad Leaders' Summit, in Manila, the Philippines. He made a number of proposals aimed at maritime security, protecting critical minerals supply chains, and enhancing trade.

The Quad meet, which was being held for the first time in a non-member country, was hosted by U.S. President Donald Trump and was attended by Australian Prime Minister Anthony Albanese and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, apart from Mr. Modi. The leaders issued a joint statement opposing economic and maritime "coercion" in the Indo-Pacific, and Mr. Modi announced that India would host the first Quad Business Forum in Mumbai in 2027.

The events started with Mr. Modi's meeting with the leaders of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) for the ASEAN-India Summit, where he said the world now needed peace, stability, and predictability more than ever. "Together, India and ASEAN represent nearly one-fourth of the world's population. That is why it is essential to ensure that our future is shaped not by competition, but by cooperation," Mr. Modi told ASEAN leaders. He also promised that India would give e-visas free of charge to ASEAN tourists. Myanmar's junta leader, President Min Aung Laing, was not invited, and the country was represented by an official.

Following this, Mr. Modi took part in the East Asia Summit, attended by the leaders of India, China, Russia, the U.S., Japan, South Korea, and the ASEAN countries, and proposed a seafarers' safety initiative. He said that "whether it is the conflict in Ukraine or West Asia, India will continue to support every effort towards peace".



Strategic group: Prime Minister Narendra Modi with leaders of other Quad nations in Manila, the Philippines, on Tuesday. REUTERS

The East Asia Summit members also issued a joint declaration on tackling cyber-crime, given the number of online fraud cases originating from Southeast Asian countries. India will host a summit on the issue at the National Forensic Sciences University in Gandhinagar and an East Asia Summit University Heads Conclave at Nalanda.

The ASEAN engagements were important as Mr. Modi had skipped the summits in Malaysia last year.

Quad leaders meet

Shortly before he left Manila, the Prime Minister met the leaders of the U.S., Australia, and Japan for the Quad Summit, which was last held in 2024.

This was the first time that all the Quad leaders have met since the U.S.-Israel attacks on Iran and the blockade in the Strait of Hormuz began more than nine months ago – in a war where at least 23 Indians, mainly seafarers, have been killed.

In remarks pointed toward China, the Quad countries strongly opposed "destabilising or unilateral actions that seek to change the status quo, including by force or coercion, which escalate tensions and undermine regional peace and stability", as well as "economic coercion, including through arbitrary export restrictions". China has recently put new restrictions on the export of critical minerals and heavy equipment like tunnel boring machines that affect Indian development activity.

The Quad leaders also announced the launch of the Quad Business Forum, which will be held in Mumbai, to bring industry leaders from the U.S., India, Australia, and Japan together.

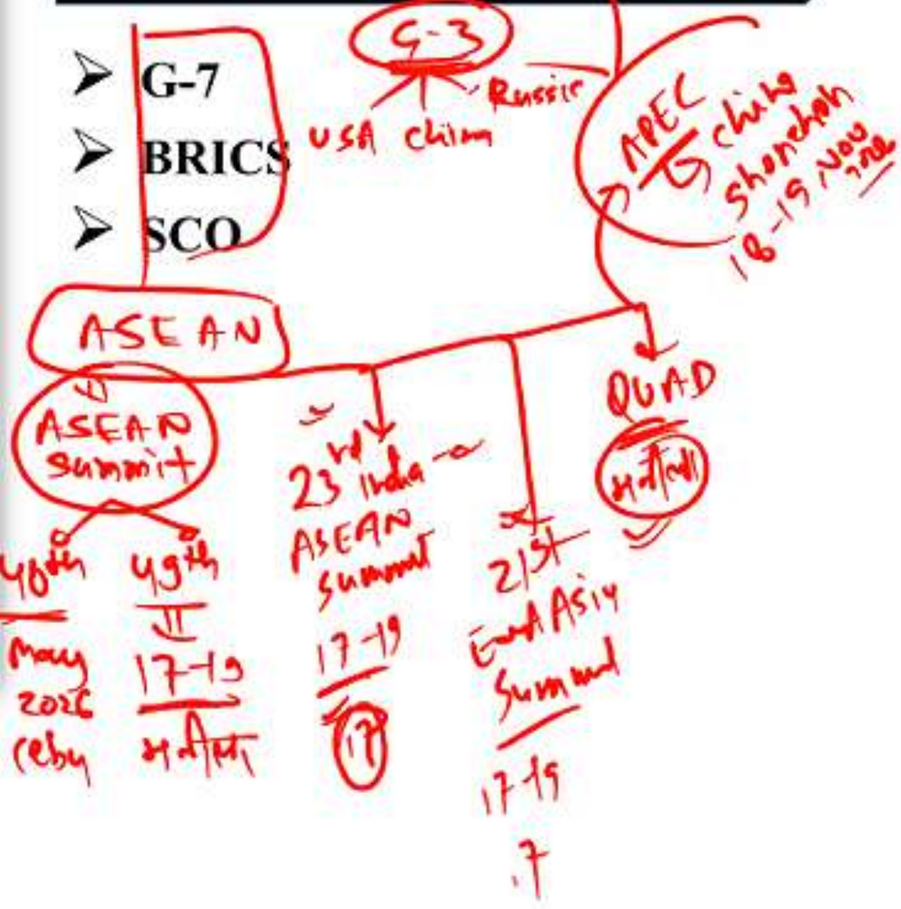
The initiative is the latest effort at economic cooperation in the region, years after another U.S. initiative, the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), was shelved. Mr. Trump also announced an Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration and said that in 2027, the navies of the Quad countries would fly patrol aircraft for the first such exercise.

Just before the Quad Summit, Mr. Trump unexpectedly spoke to the media and answered several questions, even as Mr. Modi, Mr. Albanese, and Ms. Takaichi stood silently next to him.

The U.S. President said he expected to have a "very good meeting" with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping on his next stop in Shenzhen for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit, scheduled for Thursday. He said he would push for Mr. Xi and Mr. Putin to also "get involved" to end the Russia-Ukraine and Iran conflicts.

The first three-way summit of global powers, dubbed the "G-3", will be closely watched, with Mr. Trump, Mr. Xi, and Mr. Putin expected to discuss nuclear arms control, artificial intelligence governance, and ending conflicts.

YouTube Homework



महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2026 में आयोजित 48वां और 49वां आसियान शिखर सम्मेलन, 23वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सभी फिलीपींस में संपन्न हुए हैं। नीचे इन सभी सम्मेलनों का क्रमवार विवरण, उनके मुख्य परिणाम और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की पूरी जानकारी दी गई है:
- अध्यक्षता और मुख्य विषय. इन सम्मेलनों की अध्यक्षता फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर ने की। वर्ष 2026 के सम्मेलन का मुख्य विषय "एक साथ मिलकर अपने भविष्य को दिशा देना" रखा गया।
- भारत की भागीदारी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 18 नवंबर 2026 तक फिलीपींस की यात्रा की। उन्होंने 17 नवंबर को मनीला में आयोजित दोनों प्रमुख शिखर सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- आगामी अध्यक्षता. 49वें आसियान शिखर सम्मेलन के समापन के साथ ही फिलीपींस ने वर्ष 2027 के लिए आसियान की अध्यक्षता औपचारिक रूप से सिंगापुर को सौंप दी है।

2. इन बैठकों के क्रमवार प्रमुख परिणाम और निष्कर्ष

- मनीला में आयोजित इन बैठकों से क्षेत्रीय सहयोग और भारत-आसियान संबंधों को नई गति देने वाले कई बड़े निर्णय सामने आए हैं:
- 49वें आसियान शिखर सम्मेलन के परिणाम. फिलीपींस समाचार एजेंसी के अनुसार, इस सम्मेलन में 100 से अधिक परिणामी दस्तावेजों को अपनाया गया। इसमें आसियान समुद्री केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई और डिजिटल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में बच्चों के ऑनलाइन शोषण को रोकने के लिए एक विशेष घोषणापत्र जारी किया गया। इसके अलावा, आसियान के 11वें सदस्य के रूप में तिमोर-लेस्ते के पूर्ण समावेश को दर्शाने वाले 11 धान की बालियों वाले नए ध्वज और प्रतीक चिह्न का अनावरण किया गया।
- 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के परिणाम. आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और आसियान ने दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना, संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा तकनीकी आदान-प्रदान और भारत-आसियान अंतरिक्ष हैकाथॉन की घोषणा की। भारत ने आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-वीजा सुविधा, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति बढ़ाने और वर्ष 2027 में रचनात्मक साझेदारी मंडप स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।
- 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के परिणाम. पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार, इस बैठक में ऑनलाइन घोटालों और साइबर अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने तथा भविष्य की स्थिरता पर दो महत्वपूर्ण घोषणापत्र अपनाए गए। भारत ने इस मंच पर नाविक सुरक्षा पहल, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में साइबर अपराध सम्मेलन, लोथल में समुद्री विरासत महोत्सव और नालंदा में विश्वविद्यालय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन: सदस्य देश और उद्देश्य

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संवाद और सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी।
- शामिल देशों की संख्या. ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में इस मंच में कुल 19 देश शामिल हैं। इसमें 11 आसियान सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) और 8 संवाद भागीदार देश (भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका) शामिल हैं।
- प्रमुख उद्देश्य. आसियान सचिवालय के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। यह मंच सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा और क्षेत्रीय संपर्क जैसे साझा हितों के मुद्दों पर सीधे संवाद करने का अवसर प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

U.S. blocks Chinese firms' remote access to advanced AI chips via data centres

Ananth Krishnan
BEIJING

The United States has announced new regulations aimed at curbing Chinese firms' remote access to advanced AI chips through data centres in third party countries, coming amid the scandal surrounding chipmaker Nvidia. Beijing on Tuesday slammed the new restrictions, accusing Washington of "abusing export control measures".

Nvidia's provision of chips to companies running data centres in South-east Asia has come under the spotlight amid questions surrounding founder Jensen Huang's relationship with Alice Huang, the CEO of one such Singapore-based company, Megaspeed.

With Nvidia barred from selling its most advanced chips in China, many Chinese companies instead sought access to its technology through data centres in countries such as Malaysia.

The U.S. Commerce Department's Bureau of Industry and Security (BIS) announced an interim final rule (IFR) "to address remote access" to advanced AI chips and servers, saying it was "designed to ensure that existing restrictions on access to sensitive American technology cannot be circumvented through remote computing arrangements involving data centres in third countries."

The rule states that in addition to the current licence requirements for advanced semiconductors, a licence will be required "to export, re-export, or transfer (in-country) advanced semiconductors to Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, or Brazil", which it named as "countries which present a higher-than-normal risk of diversion."

The new rule was announced days before U.S. President Donald Trump's arrival in Shenzhen for the APEC Summit.

The APEC summit will see meetings between the Presidents of the U.S. and China on its sidelines along with a rare trilateral leaders' summit with Russian President Vladimir Putin.

'Economic coercion'

China hit out at the moves, calling it "yet another case of the United States overstretching the concept of national security, and abusing export control measures to interfere in normal trade and tech cooperation between China and other countries and go after China's high-tech industry."

"Such typical economic coercion and long-arm jurisdiction run counter to the common understandings between the two countries, harm the legitimate rights and interests of Chinese companies, and disrupt global supply chains," Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said. "China will do what is necessary to firmly safeguard its legitimate and lawful rights and interests."

China's Ministry of Commerce in a statement said the new rule would affect the stability of the global semiconductor industry, adding that the U.S. was "misusing export controls to interfere indiscriminately in normal trade cooperation between Chinese enterprises and companies from other countries." "The U.S. approach runs counter to the important consensus reached by the two heads of state, undermines market rules and the international economic and trade order, and affects the stability of the global semiconductor industry and supply chain," the statement said.

Tech tussle

Nvidia's provision of chips to Southeast Asian firms is under the spotlight over a scandal involving its founder Jensen Huang

- The new U.S. rule imposes an additional licence on 5 countries presenting a "higher-than-normal risk of diversion"
- U.S. says curbs designed to ensure that restrictions on access to sensitive technology cannot be circumvented through remote arrangements
- China calls it yet another case of the U.S. "overstretching the concept of national security" to "go after" its high-tech industry

Chinese companies had sought access to Nvidia's technology through data centres in countries such as Malaysia

INS Sahyadri participates in naval exercise JAIMEX 2026

INS Sahyadri participated in the bilateral maritime exercise JAIMEX 2026 with the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) on November 13 and 14, strengthening operational cooperation and interoperability, while providing an opportunity to exchange professional experiences. According to the Indian Navy, during the exercise, *INS Sahyadri* operated alongside JMSDF ship *JS Ise*, undertaking a series of coordinated maritime engagements, including tactical manoeuvres, communication drills, and cross-deck landings. It reaffirmed the commitment of both navies to maintain peace, security and stability in the Indo-Pacific region.

JAIMEX
Japan
India

Home Assignment

- World Homeopathy Day
- PM-Mudra Yojna

RESULT MITRA

— Most Trusted IAS/PCS Institute —

UPPCS 2027

Foundation Batch (Prelims + Mains)

Start – 10th December 2026

Fee – 4999/- | Validity - 1 Year

Class Module – Live + Recorded

Special Discount

499/-

(Till 1st December)

Contact us – 9235313184, 9235446806, 7291914092, 7291914093, 7291914095, 7291914098

Contact time :-

Monday to Saturday – 10 AM – 06 PM

Thanks For Watching

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected

Learn Share Grow Together ♡

Better Students Brighter Tomorrow

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS

Small Steps Big Results